● वर्ष-2
● अंक-186
रायपुर, मंगलवार
28 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailÐcom

## इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

## प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा की है कि आगामी धान खरीदी के मौसम में प्रति एकड़ 15 क्विंटल के स्थान 20 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि आगामी खरीफ सीजन के धान को 28 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। यह घोषणा इस मायने में अच्छी है कि किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिल रहा है और एक-एक दाना धान की खरीदी सरकार करेगी। लेकिन इन दोनों घोषणा के बीच में एक अंतर आ रहा है। अभी राज्य सरकार धान को केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2040 रु. की दर से ही खरीद रही है। लेकिन किसानों को जो फायदा हो रहा है वह राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9000 रु. प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी मिलने के कारण है। अभी प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है तो प्रति क्विंटल 600 रु. का अतिरिक्त लाभ किसानों को रहा है। अब मुख्यमंत्री किसानों को फसल का 2800 रु. प्रति क्विंटल देना चाहते हैं और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान भी खरीदना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के ऊपर प्रति क्विंटल इनपुट सब्सिडी घटकर 450 रु. हो जाएगी। अगर ऐसा है तो शीघ्र भूपेश सरकार यह भी घोषणा करने वाली है कि प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी और यह बढ़ोत्तरी 5 हजार रुपए प्रति एकड़ होगी, तब किसानों को 2800 रु. प्रति क्विंटल की दर से भाव मिलेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदना चाहती है लेकिन क्या प्रदेश में पैदावार धान की इतनी है भी? अभी बजट सत्र में जारी सरकारी आंकड़े के मुताबिक प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता 35 क्विंटल से थोड़ा ज्यादा है। अगर 20 क्विंटल के हिसाब से धान का उत्पादन देखे तो प्रति हेक्टेयर 50 क्विंटल धान का उत्पादन करना होगा। राज्य बनने के बाद कभी 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन नहीं हुआ। दूसरी ओर प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है इसीलिए गौठानों में गोबर खरीदकर उसका वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है और यह वर्मी कम्पोस्ट प्रति एकड़ 30 बोरी लेना अनिवार्य है। सभी जानते है कि रसायनिक खाद का उपयोग नहीं करने से उत्पादन कम होता है फिर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी सरकार कैसे करेगी? इसका मतलब है कि आसपास के राज्यों से धान की तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। तस्करी तो अभी भी हो रही है इसकी मात्रा का आंकलन करना कठिन भले ही है लेकिन कई एजेंट करोड़ों, अरबों रुपए धान की अवैध तस्करी से पैसा कमा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को हानि होती है और यह भार राज्य की जनता पर पड़ता है। इसीलिए सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए।

# सावरकर का अपमान कांग्रेस को पड़ेगा महँगा

## उद्धव की राहुल गांधी को चेतावनी, महाविकास अघाड़ी से अलग होने की तैयारी में!

वीर सवरकर को लेकर राहुल गांधी भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं। हाल में ही उन्होंने सावरकर को लेकर फिर से बयान दिया था। अब इसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र मे महा विकास आघाड़ी के शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वह हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाह दी कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस पर हमला बोला ही है साथ ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान भी कांग्रेस के विरोध में आये हैं। केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो आपको बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें। उन्होंने कहा कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) तीन दलों- शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन है, जिसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी

था। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, ''सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेलीं। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं। यह बलिदान एक प्रतीक है।'' ठाकरे ने कहा, ''मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि, आपको जानबूझ कर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव, आखिरी चुनाव होगा।''

दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वीर सावरकर जी का बार-बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का देश की आजादी के लिए जो योगदान है, वो सभी को पता है। उनका बार-बार अपमान करने से राहुल गांधी को बचना चाहिए।

वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। इस बारे में संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से हमें ठेस पहुँची है तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं।

दूसरी ओर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया है, उससे उन्होंने देश के करोड़ों राष्ट्रभक्त लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है।

लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने आए। इस दौरान राहुल गांधी से माफी को लेकर सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगते। इसके बाद भाजपा राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है।

### सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वतंत्र वीर सावकर जी का बार-बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर का देश की आजादी के लिए जो योगदान है, ये सभी को पता है। उनका बार-बार अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही वीरों के योगदान से भारत को आजादी मिली। हम राज्य में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के योगदान के बारे में बात करने के लिए हम राज्य के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। साथ ही, हम सावरकर का अपमान करने वालों का विरोध करेंगे। वहीं, आज भाजपा-शिवसेना सांसदों ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद में शिवाजी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी सेलुलर जेल में काटी, क्या वे कभी सेलुलर जेल गए हैं? राहुल गांधी एक बार सेलुलर जेल जा के देखें तब उन्हें पता चलेगा कि सावरकर क्या है?

# हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 को संसद की मंजूरी

**नई दिल्ली।** संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन संसद में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी रहा। आज भी दोनों सदनों में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर कांग्रेस से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के नेता दोनों ही सदनों में काले कपड़े पहने हुए नजर आए। वहीं संसद में भी विपक्षी एकजुटता देखने को मिली। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 28 मार्च की सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन हंगामे के बीच ही कुछ कामकाज भी किए गए हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष

2023-24 का बजट पारित किया गया। वहीं, वित्त वर्ष 2320 के लिए बजट के साथ ही फाइनेंस विधेयक को भी पारित कर दिया गया। राज्यसभा से इसे वापस लोकसभा भेजा गया। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद शाम 4:00 बजे शुरू की गई थी। सदन ने हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को स्वीकृति दी। एक बार के स्थगन के बाद शाम चार बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागज सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान काले परिधान पहने कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य अडाणी मुद्दे पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग भी कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। संशोधन में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) पर कर की दर के संबंध में एक त्रुटि के सुधार का प्रस्ताव है। हंगामे के बीच ही सदन ने राज्यसभा के भेजे गये संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि उसने वेदों की शिक्षा के लिए देश में पांच राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। लोकसभा में सी पी जोशी के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डा. सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3,497 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में दीपक बैज के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।

**प्रमुख समाचार**

### राहुल को 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

**नई दिल्ली।** कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान ही उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सबके बीच राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की ओर से यह नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। लेकिन मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनके सांसदी अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इसी कारण बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी के प्रति भाजपा की नफरत को दर्शाता है।

### सुप्रीम कोर्ट से लालू को राहत, जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस से इनकार

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को लालू प्रसाद यादव को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने

झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और इसे लंबित अपील की सूची में डाल दिया। इस मामले में लालू यादव को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह नोटिस जारी नहीं कर रही है बल्कि मामले को सीबीआई द्वारा दायर इसी तरह की लंबित अपील के साथ जोड़ रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की, लेकिन पीठ ने कहा कि वह मामले की एक साथ सुनवाई करेगी और नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक नहीं है। सीबीआई ने अपनी याचिका में लालू यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी।

### वामपंथी विधायक भारत में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान-चीन से रखते हैं संबंध-रतन

**नई दिल्ली।** त्रिपुरा के संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने विधानसभा में विपक्षी सीपीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वामपंथी विधायक भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान, चीन से संबंध रखते हैं। त्रिपुरा के मंत्री ने कहा कि आपको चाहिए कि आप भारत से प्यार करें। बीजेपी नेता ने सीपीएम के बारे में कहा कि आप यहां रहते हैं लेकिन पाकिस्तान और चीन से संबंध बनाकर रखते हैं। देश से प्यार करो...बाकी सब से पहले एक राष्ट्रवादी बनो। सीपीएम ने कांग्रेस के साथ साझेदारी में विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। 24 मार्च को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नाथ ने पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं के छंदों का जिक्र किया और कहा कि भाजपा विधायकों ने पहले देश और समाज के बारे में सोचा। नाथ ने सीपीएम के राज्य सचिव और विधायक दल के नेता जितेंद्र चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह खुद एक आदिवासी नेता होने के बावजूद एसटी-आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि कम्युनिस्टों ने अपना जनजातीय समर्थन आधार खो दिया था।

### अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी

**नई दिल्ली।** खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भारत में लगातार छापेमारी जारी है। वहीं भगोड़े अमृतपाल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सुरक्षा

एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल भारत के पड़ोसी देश नेपाल में छुपा बैठा है और वहां से किसी तीसरे देश में भागने की फिराक में है। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि भगोड़े कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश में भाग जाने की अनुमति नहीं दी जाए और यदि वह भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य नकली पासपोर्ट का उपयोग करके भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इकोनॉमिक टाइम्स ने काठमांडू पोस्ट अखबार के हवाले से बताया है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को कांसुलर सेवा विभाग को भेजे पत्र में सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि यदि सिंह नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। पत्र ने प्राप्त पत्र की प्रति का हवाला देते हुए इस बात का खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है।

### शहीद असिस्टेंट प्लाटून कमांडर का पार्थिव शरीर पहुंचा मेकाज, चॉपर से भिजवाया गया गृहग्राम

**बीजापुर।** बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में आज सुबह सड़क सुरक्षा के लिए गस्त में निकले

सीएएफ के जवान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी के चपेट में आ गए। इस घटना में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए। वहीं, शव का पीएम करने के बाद भैरमगढ़ से मेकाज भेजा गया। जहां शव को एंबॉलिंग करने के बाद चॉपर से गृहग्राम भिजवाया गया। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी घटना पर दुख जताया था। बता दें कि, 27 मई की सुबह जिला बीजापुर के थाना मिरतुर क्षेत्रांतर्गत न्यू कैम्प एटेपाल एवं तिमेनार से एरिया डॉमीनेशन के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान प्रातः लगभग 7:40 बजे तिमेनार-एटेपाल के मध्य माओवादियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ के एपीसी विजय यादव 19वीं वाहिनी डी कंपनी तिमेनार शहीद हो गये। बताया जा रहा है की एपीसी विजय यादव 21 अक्टूबर 1986 को सेवा में आए थे। इसके अलावा अपनी बेटी व दामाद के साथ धरमपुरा दुर्गा मंदिर के सामने निवास कर रहे थे। जबकि उनका मूल घर राजपुर पोस्ट हल्दी जिला बलिया में है।

# विपक्ष को एकजुट करने में राहुल का व्यक्तित्व बड़ी अड़चन

**रशीद किदवई**

आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी करीब साल भर का समय बाकी है, लेकिन देश का राजनीतिक तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की अदालत से मानहानि के एक आपराधिक मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया है, जिससे कांग्रेस की राजनीति अभी एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। अभी तक गैर-भाजपा दल कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व सौंपने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन 23 मार्च की घटना के बाद कांग्रेस को गैर-भाजपा विपक्षी दलों का व्यापक समर्थन मिला है।

कह सकते हैं कि यह कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन क्या कांग्रेस इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने में सक्षम है? क्या वह सभी गैर-भाजपा दलों को साथ लेकर भाजपा को टक्कर दे पाएगी? इसमें एक बड़ी अड़चन खुद राहुल गांधी का व्यक्तित्व है। इस घटना के बाद बाकी विपक्षी नेताओं की तुलना में उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है, लेकिन इस कद के साथ उन्हें न्याय करना होगा। और यहीं पर कई अड़चनें दिखाई देती हैं।

उन्हें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार जैसे विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, जो बड़ा कठिन काम है। जबसे राहुल राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक तरह से दूरी बनाकर रखी। एमके स्टालिन को छोड़ दें, तो बाकी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ कभी राहुल ने गर्मजोशी नहीं दिखाई। बल्कि कई बार उन्होंने अपने बयानों से अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के लिए मुश्किल ही खड़ी कर दी, जैसे सावरकर को लेकर दिए गए बयान के जरिये उन्होंने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को कठिनाइयों में ही डाल दिया। मगर अच्छी बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अनुभवी

और सुलझे हुए नेता हैं, जिनके तमाम गैर-भाजपा, गैर-राजग दलों से बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे श्रीकृष्ण, क्या खरगे वह भूमिका निभा पाएंगे।

राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, उसके दो पहलू हैं। एक तो अदालती पहलू है और दूसरा राजनीतिक पहलू है। हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष लड़ता है, तो वह लड़ाई लंबी होती है। उस लड़ाई को सतत जारी रखने के लिए सिविल सोसाइटी का सहयोग बहुत जरूरी होता है। ऐसा जेपी आंदोलन में भी हुआ था, राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह के अभियान में भी हुआ था, और हाल ही में अन्ना आंदोलन के दौरान भी हमने सिविल सोसाइटी की सक्रिय भूमिका देखी थी। यहीं पर कांग्रेस की जमीन कमजोर मालूम पड़ती है। अतीत में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी का राजनीतिक फायदा उठाया हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय जरूर सौ-डेढ़ सौ के करीब सिविल सोसाइटी उनके साथ जुड़ी थी, पर उनमें से अधिकांश गैर-राजनीतिक सिविल सोसाइटी थीं। अब कांग्रेस या राहुल गांधी उन सबको अपने साथ जोड़ पाएंगे, इसे लेकर संशय है।

तीसरी बात, भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस को उदार हृदय से एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को शामिल करना चाहिए, जिनकी राजनीतिक साख दलों से ऊपर है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं को इसमें सक्रिय भूमिका में लाना चाहिए। बेशक थोड़े-बहुत वैचारिक या मुद्दे आधारित मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन सबको एकजुट करके पटरी पर लाना बहुत कठिन, मगर महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया के जमाने में एक और चीज महत्वपूर्ण है-समय, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। जैसे, अभी बहुत से लोगों (जो घोषित रूप से कांग्रेस या भाजपा के समर्थक नहीं हैं) को लगता है कि राहुल गांधी भले ही उतने परिपक्व नेता न हों, लेकिन आपराधिक मानहानि के मामले में जिस तरह उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई, वह अनुचित थी। लोगों को लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा सहित विभिन्न दलों में बहुत से ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अनाप-शनाप टिप्पणियां की हैं, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली। ऐसा सोचने वाले करोड़ों लोग हैं, जो किसी पार्टी के समर्थक नहीं होते हैं, लेकिन चीजों को देखते-समझते और उनका संज्ञान लेते हुए वोट डालते हैं। तो ऐसे वर्ग का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्ष को तेजी से और चरणबद्ध तरीके से अपना अभियान चलाना होगा, लेकिन इस घटना को तीन दिन बीत गए हैं, लेकिन उस तरह का एहसास नहीं हो रहा है। राजीव गांधी के समय जिस तरह विपक्ष ने एकजुट होकर संसद से इस्तीफा दे दिया था, वैसी पहल हमें अभी नजर नहीं आ रही है। बाकी विपक्ष को तो छोड़िए, कांग्रेस के भीतर भी उतना आक्रोश नहीं दिखता। यदि किसी रणनीति के तहत कानूनी सरगर्मी नहीं हो रही है, तो राजनीतिक सरगर्मी तो दिखनी चाहिए, अन्यथा यह मामला दबकर रह जाएगा। राहुल गांधी व्यक्तिगत स्तर पर सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता में अदाणी के साथ भाजपा के कथित संबंधों पर बोला। लेकिन उसमें भी जब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह कोई तथ्यात्मक और चौंकाने वाली बात सामने नहीं आएगी, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा।

# मुख्यमंत्री ने किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का अंतरण

## वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों को दी बड़ी सौगात, छ.ग. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 एप का शुभारंभ

**बेमेतरा।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी रुरल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रदेश स्तर में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लोकार्पण किया। बेमेतरा जिले में महात्मा गांधी रुरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत बेरला के ग्राम रामपुर (भांड़) एवं जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम अमलडीहा में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वर्चुअल कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक श्री पुनू लाल मोहले एवं धरमजीत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

जिले के रामपुर (भांड़) में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बेमेतरा श्री आशीष कुमार छाबड़ा एवं कलेक्टर बेमेतरा श्री पदुम सिंह एल्मा ने महात्मा गाँधी और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में माल्यार्पण एवं दीप जलाकर राजगीत अरपा पैरी के धार महा नदी है अपा.....के साथ कार्यक्रम की शुरुवात की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार बेरला मनोज गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला स्वप्निल ध्रुव, वरिष्ट जनप्रतिनिधि बंशी पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष बेरला हीरा देवी वर्मा, सहित जनप्रतिनिधिगण एवं आसपास के ग्रामीणजन उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि बेमेतरा जिले में जनपद

पंचायत बेमेतरा के अन्तर्गत गांगपुर (ब) एवं झालम, जप साजा के अन्तर्गत ग्राम राखी एवं ओड़िया, नवागढ़ के अन्तर्गत अमलडीहा एवं मोहतरा तथा जनपद पंचायत बेरला के अन्तर्गत सांकरा एवं रामपुर (भांड़) में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। जिसमें दाल मिल एवं दाल प्रसंस्करण इकाई, फेन्सिंग वायर यूनिट, सिलाई मशीन यूनिट, साबुन निर्माण, फर्नीचर निर्माण यूनिट, फिनाइल यूनिट, आटा मिल, दोना पत्तल यूनिट, चना-मुर्रा यूनिट, जैविक कीटनाशक, उत्पादन यूनिट आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी। जिसके तहत ग्रामीण आजीविका और स्वरोजगार से सम्बंधित इकाइयों का भविष्य में विस्तार किया जाएगा। बेमेतरा जिले में रीपा अन्तर्गत 19 उद्योग शुरु हो रहे हैं। इन उद्योगों में कुल 254 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 107 महिलाएं एवं 147 पुरुष होंगे। रामपुर भांड़ में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने पोहा मिल का शुभारंभ किया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क और अन्य योजनाओं का बटन दबाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों के खाते में 149.92 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 2325041 किसानों के खाते में चौथी किस्त की राशि 174020.73 लाख रुपये का अंतरण किया गया। जिसमें बेमेतरा जिले के 140319 किसानों के खाते में चौथी किस्त की राशि 104 करोड़ रुपये अंतरित हुई। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना की 6.34 करोड़ रुपये की राशि का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ, छ.ग. बेरोजगारी भत्ता योजना का वेब पोर्टल और छ.ग. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 एप का शुभारंभ किया एवं नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और सम्बोधित करते हुए कहा कि ये किसान, मजदूर और युवा मन के भरोसा के सम्मेलन हे अउ ये भरोसा अभी के नई हे बल्कि चार साल के हे। गांव एवं नगर पंचायत (बड़ा कस्बा) के बीच मे ज्यादा फर्क नही होता है इसलिए नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को भी लाभांवित करने के लिए नगरीय राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। इससे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले किसानों को आर्थिक लाभ होगी। राज्य विकास के लक्ष्य को सबको मिलकर हासिल करना है। शासन ने सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया है। प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूर श्रमिक को सहायता राशि दी जा रही है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, कोटवार आदि का मानदेय बढ़ाया गया। नये आत्मानन्द स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे साथ ही पत्रकार सुरक्षा योजना लागू किया गया। जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम जैविक राज्य के दिशा में आगे बढ़ते जाएँगे। आज के समय में व्यापार व्यवसाय और उद्योग के साथ-साथ किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधरी है। हमारा प्रयास सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना है। आज के इस रीपा कार्यक्रम की शुरुआत होने से प्रदेश के युवाओं महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रीपा के माध्यम से परंपरागत उद्योगों का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अब 20 क्विंटल धान बेचने से किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर हमारे किसान भाईयों के दुख: दर्द को समझा है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी आज किसानों के लिए खुशी का दिन है, भूपेश है तो भरोसा है ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामुहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाना है। रासायनिक खादों के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं इसलिए जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री रवींद्र चौबे अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले चार साल में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों को दिया है। प्रदेश में 2640 रुपये में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इस साल से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी, भूपेश है तो भरोसा है। प्रदेश सरकार ने विगत 4 साल में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाया है। सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ कर, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभ दिलाया जा रहा है, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की बोनस राशि किसानों के खाते में सीधा अंतरित किया जाता है। जिससे हर वर्ष किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

### मुख्यमंत्री ने छुरिया में पंचायत कैफे का किया शुभारंभ

**राजनांदगांव।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड मुख्यालय छुरिया में पंचायत कैफे का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर फरा तथा मिलेट्स व्यंजन रागी के हलवा का स्वाद लिया। उन्होंने इस मौके पर बिहान महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों को प्रशंसा की। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री का कैफे के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की पहल पर बिहान स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने परंपरागत छत्तीसगढ़ी एवं मिलेट्स व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद पंचायत छुरिया के परिसर में पंचायत कैफे की शुरूआत की गई है। पंचायत कैफे के अवलोकन के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जिले में चलाए जा रहे पंचायत कैफे के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छुरिया में पंचायत कैफे के संचालन के लिए 5 महिला स्व-सहायता समूह पदम तुलसी स्व-सहायता समूह बम्हनीचारभाठा, भवानी स्व-सहायता समूह, शिकारीमहाका, मां शक्ति स्व-सहायता समूह तेन्दूटोला, जय मां संतोषी स्व-सहायता समूह कुमर्राछुरिया, जय गुरूदेव स्व-सहायता समूह जंगलपुर को बैंकों के माध्यम से 2 लाख 50 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करायी गई है। छुरिया के पंचायत कैफे में छत्तीसगढ़ी परंपरागत व्यंजन चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, अनरसा, मिलेट व्यंजन, इडली, दोसा एवं अन्य फास्टफूड व्यंजन की बिक्री की जा रही है। गौरतलब है कि डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अर्जुनी में पंचायत कैफे का संचालन किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दलेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री धनेश पाटिला भी उपस्थित थे।

# राहुल के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करना भाजपा की स्तरहीन राजनीति : राजेन्द्र साहू

**दुर्ग।** राहुल गांधी के बयान को भाजपा द्वारा ओबीसी विरोधी बयान बताए जाने पर जिला सहकारी केन्दीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष व छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने इसे स्तरहीन राजनीति का नया अध्याय करार दिया है।

राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस विशेष रूप से गांधी परिवार ने आजादी के बाद से हमेशा एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए बड़े फैसले किए। कांग्रेस ने ही वाले भाजपा नेता किस मुंह से नौकरियों में आरक्षण दिया गया। कांग्रेस की पंडित नेहरू ही विधेयक को रोका जा रहा है।सरकार ने देश में इन वर्गों की भलाई के लिए बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को लागू किया और बड़े-

बड़े कल कारखाने खोले गए, जिसमें इन वर्गों को आरक्षण का लाभ देते हुए व नौकरियां दी गई।

दूसरी ओर भाजपा नेता म अक्सर यह बयान देते हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। पिछड़ों को दिये जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने वाले भाजपा अ बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। एसटी और ओबीसी व अल्पसंख्यक प विधेयक रोकने के लिए किसने अड़ंगे स संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश का लगाए, यह सभी जानते हैं। कई बीजेपी नेताओं ने स्वीकार संविधान तैयार किया, जिसमें इन वर्गों को सरकारी भी किया है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के कारण इन वर्गों को आरक्षण, सब्सिडी सहित आजादी के बाद से पिछड़े वर्गों नेताओं को पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के कई योजनाओं का लाभ दिया। के उत्थान के लिए गांधी आरक्षण समाप्त करने का विचार रखने परिवार ने ही बनाई योजनाएं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के हितचिंतक बन रहे हैं। भाजपा ने हमेशा पिछड़े वर्गों वर्ग के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण का राजेंद्र ने कहा कि आजादी के बाद का विरोध किया।

# भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में चार कांग्रेसी गिरफ्तार

**कोरबा।** छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में जिला युवक कांग्रेस के महासचिव सहित चार युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से 25- 25 हजार रुपयों की जमानत पर इन्हें रिहा कर दिया गया।

गुरुवार 22 मार्च 2023 को केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर मान हानिकारक टिप्पणी के मामले में सूरत गुजरात के सीजीएम कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। शुक्रवार 23 मार्च को राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी के खिलाफ आये इस फैसले के विरोध में शुक्रवार को कोरबा के युवक कांग्रेस

कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान पार्टी कार्यालय में घुसकर भाजपा के बैनर पर कालिख फेंकी गई थी और उसे फाड़ दिया गया था। साथ ही तोड़फोड़ भी की गई थी।

घटना की सूचना पाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला कार्यालय पहुंचे थे। घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेने के बाद भाजपा नेता एफआई आर दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन पुलिस थाना के सीएसईबी पुलिस चौकी गए, लेकिन देर रात तक उनकी एफ आई आर नहीं लिखी गई। इससे आक्रोशित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रात में पुलिस चौकी का घेराव और चक्का जाम कर दिया था। आधी रात तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने घटना की लिखित शिकायत लेकर जांच के पश्चात कार्रवाई का आश्वासन दिया था। शनिवार को भाजपा नेताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण से भेंट कर कार्रवाई की मांग की थी।

रविवार 25 मार्च को दिनभर चली जांच के बाद और भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ का वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने युवक कांग्रेस के चार नेताओं को शाम के वक्त गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं में जिला युवक कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास सहित आशीष गुप्ता, जयकिशन पटेल और अनिल खूंटे शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद इन्हें सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें जमानत मिल गई।

**छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार**

### बाना परघौनी कर पंचमी मनाई गई

**भिलाई।** मां कल्याणी शीतला मंदिर, मरोदा, रिसाली में चल रहे भव्य वासंती चैत्र नवरात्रि महापर्व में पंचमी पूजा एवं बाना परघौनी पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। आयोजन समिति कार्यकर्ताओं द्वारा रिसाली गांव से भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, और मंदिर परिसर में बाना का स्वागत कर स्थापना की गई। संध्या महाआरती पश्चात श्री शिवम महिला भजन मंडली हिंद नगर, रिसाली एवं गोंडवाना साहित्य एवं सांस्कृतिक विंग, रिसाली-मरोदा, द्वारा माता जस गायन की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात इस दिन की प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुति 'महतारी के कोरा' (देऊरगांव, साजा) ने देर रात तक उपस्थित दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, समाजसेविका एवं धर्मपत्नी सांसद दुर्ग रजनी बघेल, डॉ. घनश्याम निषाद, अध्यक्ष निषाद समाज दुर्ग, लिलेश देशमुख, निज सचिव सांसद दुर्ग एवं पार्षद विधि यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन समिति सचिव शैलेंद्र शेण्डे 'शैली' ने किया।

### प्रदेश कांग्रेस सरकार किसानों की सच्ची हितेषी : श्याम वर्मा

**दुर्ग।** पिछड़ा वर्ग कॉंग्रेस के दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्याम वर्मा ने छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसान हित मे लिये गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। जिसमे छग की कांग्रेस सरकार ने किसानो से 15 क्विंटल की जगह अब 20 क्विंटल धान खरीदी विभिन्न सोसाइटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही अगले साल बाजार में गजब की रौनक आयेगी साथ ही छग पूरे भारत मे सबसे समृद्ध राज्य के रूप में जाना जायेगा।श्री वर्मा ने आगे कहा कि यह निर्णय मात्र किसान हित मे नही है।बल्कि छग की आम जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करने की क्रान्तिकारी पहल है।जिसका दूरगामी परिणाम काफी सुखद होगा।इस ऐतिहासिक फैसले के लिये छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित मंत्री मण्डल के सभी सदस्यों का आभार माना है।जिन्होंने छग के किसानों के हित मे अपनी सच्चे हितेषी होने की भूमिका निभाई है।

### युवा कांग्रेस के सौंपे ज्ञापन पर कलेक्टर जनदर्शन में कार्यवाही

**दुर्ग।** छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के जिला महासचिव दुर्ग ग्रामीण फिरोज खान आजाद द्वारा 6.2.2023 को समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जनदर्शन में शिकायत किया था जिस पर लक्ष्मण तिवारी आईएएस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग को अवैध प्लाटिंग के मामले में धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर दुर्ग तिवारी द्वारा शिकायत सही पाये जाने पर खसरा नंबर 496/1 156 व 151/1 पर कार्रवाई करते हुए जमीन दलाल महावीर डेवलपर्स के मालिक योगेश पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

### केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से नक्सली बौखलाए

**बस्तर।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी किया है। इसमें माओवादी नेता का आरोप है कि, केंद्रीय गृह मंत्री सीआरपीएफ को आदिवासीयों और माओवादियों के खिलाफ यह कहकर भड़का रहे हैं कि माओवादी देश विरोधी और आतंकवादी हैं। माओवादी नेता ने कहा है कि, हमारा युद्ध सीआरपीएफ के खिलाफ नहीं बल्कि शासक वर्ग और उस हुकूमत के खिलाफ है, जो जनता पर अत्याचार करते हैं। नक्सली नेता ने गृह मंत्री के उस बयान का भी खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, माओवाद से जंग आखिरी चरण पर है और आदिवासी विकास में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि, माओवाद इलाकों में 125 और सिर्फदो सालों में 53 कैम्प स्थापित कर सम्पूर्ण बस्तर को सैनिकीकरण कर दिया गया है। गृह मंत्री के इस दौरे के बाद माओवाद इलाकों में हवाई हमले तेज हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा हवाई हमलों के लिए उकसा रही है।

### प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने की कोशिश, भाजपा-कांग्रेस में हुई झूमा-झटकी

**कुरूद।** मोदी सरनेम मामले में गुजरात कोर्ट के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देने और लोकसभा में सदस्यता से बर्खास्त करने के फैसले का छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में युवा कांग्रेसियों ने विरोध किया है। कुरूद में विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवव्रत साहू के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से चंद कदमों की दूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आरएसएस का निकर पहनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन करने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा-कांग्रेस के बीच झूमाझटकी हो गई। रैली की शक्ल में कांग्रेस भवन से निकले कांग्रेसियों ने कारगिल चौक होते हुए भाजपा कार्यालय के पास विरोध में आवाज बुलंद कर कालिख पोतने और मोदी के पुतला जलाने की कोशिश की। उधर भाजपा कार्यालय के तरफ जाते देख भाजपाइयों ने दौड़ाड़े हुए कांग्रेसियों को रोकने बीच सड़क पर उतर गए और जमकर झड़प हो गई।

# बेमेतरा विस क्षेत्र में बहेगी करोड़ों के विकास कार्यों की धारा: विधायक

**बेमेतरा।** बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयासों से बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को एक बार फिर से विकास कार्यो की सौगात मिली है,इस बार विधानसभा क्षेत्र में कार्यों को यह मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत कुल 39 विकास कार्यो के लिए 01 करोड़ 49 लाख 79 हजार की स्वीकृति मिली है वही छ.ग.राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण योजना के अंतर्गत कुल 10 विकास कार्यों के लिए 40 लाख 50 हजार रुपए मिली है,जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मला घाट, सामुदायिक भवन,तथा सी.सी. रोड़ निर्माण तालाब सौंदर्यीकरण, मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय शेड निर्माण के काम हो सकेंगे विधायक आशीष छाबड़ा ने कार्यों के स्वीकृत होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान.भूपेश बघेल जी,पंचायत मंत्री मान.रविन्द्र चौबे जी तथा लोकनिर्माण मंत्री मान.ताम्रध्वज साहू जी एवं श्री दलेश्वर साहू जी अध्यक्ष छ.ग.राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया है ।



ब्लाक बेमेतरा में ग्राम पंचायत बसनी में सी.सी.रोड निर्माण दशरु के घर से बुधराम के घर तक राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत खुडमुड़ी में सी.सी.रोड़ निर्माण सांस्कृतिक मंच के पास राशि 5.20 लाख,ग्राम पंचायत बहेरा(कु.) सी.सी.रोड़ निर्माण कलाराम से घर के पास राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत बाबामोहतरा सी.सी.पितामबर के घर थानू साहू के घर तक राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत डूंडा सी.सी.रोड़ निर्माण जैतराम से तालाब तक राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत हथमुड़ी में सी.सी.रोड़ निर्माण प्राथ.शाला से तामेश्वर के घर तक राशि 2.60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं

वहीं दारगांव जोन ग्राम पंचायत मोहरेगा सामुदायिक भवन निर्माण (सतनामी पारा) राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत मोहलाई के आश्रित ग्राम टठिया में सामुदायिक भवन निर्माण (शीतला मंदिर के पास) राशि 6.50लाख, ग्राम पंचायत खजरी सी.सी.रोड निर्माणड्डमानक दास के घर से श्रवण रावत के घर तक राशि 2.60लाख रुपए स्वीकृत किए गए

ब्लाक बेरला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहिंगा के आश्रित ग्राम नवागांव में सामुदायिक भवन निर्माण(गोड पारा) राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत बोरिया सामुदायिक भवन निर्माण राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत गोडगिरी सामुदायिक भवन निर्माण (साहू पारा) राशि 6.50 लाख, ग्राम पंचायत सांकरा सामुदायिक भवन निर्माण (साहू पारा) राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत भिलौरी सामुदायिक भवन निर्माण (कबीरा पारा) राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत सिंघौरी सामुदायिक भवन निर्माण (साहू पारा) राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत सलधा सामुदायिक भवन निर्माण राशि 6.50 लाख,ग्राम पंचायत बहेरघट सामुदायिक भवन निर्माण (साहू पारा) राशि 6.50लाख,ग्राम पंचायत किरीतपुर सी.सी.रोड़ (शीतला मंदिर के पास) राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत लावातरा(ढा) सी.सी.रोड़ निर्माण (प्रगति चौक) राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत भरचटटी सी.सी.रोड़ निर्माण राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत हरदी सी.सी.रोड निर्माण राशि 2.60 लाख,ग्राम पंचायत तीलई सी.सी.रोड़ निर्माण शिवनाथ साहू के घर से विदेशी साहू के घर तक राशि 2.60 लाख रुपए तथा आदि कार्यों के लिए रूपए मंजूर किए गए।

# प्रेशर आईईडी की जद में आने से सीएएफ के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद

**बीजापुर।** बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह प्रेशर आईईडी की जद में आकर एक सीएएफ के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गये।

जानकारी के मुताबिक जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र के तिमेनार कैम्प से सोमवार कि सुबह सीएएफ के जवान सड़क निर्माण कि सुरक्षा में एटेपाल की तरफ निकले हुए थे। इसी बीच एटेपाल कैम्प से करीब एक किमी दूर टेकरी के पास प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हो गया।

जिसकी चपेट में आने से सीएएफ के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर (एपीसी) विजय यादव शहीद हो गये। शहीद जवान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के राजपुर के रहने वाले हैं। शहीद के पार्थिव शरीर को भैरमगढ़ लाया जा रहा है। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर

दिया जाएगा। भैरमगढ़ से चॉपर से पार्थिव शव को गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा।

#### मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने पर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव की शहादत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को दु:खद बताते हुए नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की एक टीम आज सुबह मिरतुर थाना क्षेत्र में एरिया डामिनेशन के लिए निकली थी। मुख्यमंत्री ने शहीद यादव के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार

**नईदिल्ली।** रविवार को दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहा था। इसी को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री, अगर कुछ लोगों को उनके बारे में ऐसी बातें करनी हैं तो जनता उन्हें पहले की तरह ही करारा जवाब देगी। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। मुझे जेल में डाल दो लेकिन सच तो यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि आज नई विमान सेवा पंजाब के अमृतसर से इंग्लैंड के गैटविक तक शुरू कि गई है। यह विमान सेवा हफ्ते में 3 दिन चलेगी। यह अमृतसर का इंग्लैंड से तीसरा जुड़ाव होगा। यह अमृतसर पूरे पंजाब के लिए नहीं विकास के द्वार खोलेगा। 2013-2014 तक सिर्फ 6 शहर जुड़े थे अब यह संख्या 21 हो चुकी है।

## सावरकर को जानने राहुल को 7 जन्म लेना पड़ेगाः गिरिराज

**नईदिल्ली।** राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस जबरदस्त तरीके के भाजपा और केंद्र की सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच भाजपा की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। काले कारनामे, फिर काले कपड़े और अब ये काले जादू तक जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में इतना अहंकार है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी और कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। एक व्यक्ति की वजह से ये सत्र नहीं चलने दे रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी सेलुलर जेल में काटी, क्या वे कभी सेलुलर जेल गए हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार सेलुलर जेल जा के देखें तब उन्हें पता चलेगा कि सावरकर क्या है?

## गांधी परिवार खुद को संविधान से ऊपर मानता है : शेखावत

**नई दिल्ली।** भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को सबसे अलग मानता है और ये खुद को संविधान से भी ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने में भाजपा या सरकार का कोई हाथ नहीं है और कानून ने अपना काम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि न्यायिक और कानूनी कार्रवाई पर कांग्रेस नेता रोना-धोना कर रहे हैं, जो दिखाता है कि गांधी परिवार खुद को देश की न्यायिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान से खुद को ऊपर मानता है। शेखावत ने कहा कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को कई मौके दिए थे, जिसमें उन्हें उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। उनका मानना था कि न्यायपालिका उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत नहीं करेगी। कानून ने अपना काम किया और भाजपा या सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है।

## अदाणी समूह मामले में महुआ मोइत्रा ने सरकार को घेरा

**नईदिल्ली।** अदाणी समूह मामले पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को दुबारा प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की आलोचना की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय से राज्यसभा में एक लिखित उत्तर का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों स्वामित्व वाली शेल कंपनियों के बारे में डेटा नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सरकार अदाणी के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है? वित्त मंत्रालय को शेल फर्म की परिभाषा नहीं पता है। आरएस में लिखित जवाब कहता है कि कोई सुराग नहीं है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। महुआ मोइत्रा और अन्य विपक्षी नेता सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं क्योंकि गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए अपतटीय शेल कॉस का उपयोग करने के लिए जनवरी में बुलाया गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदाणी समूह के शेयरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है।

## भाजपा ने ऐसे कराई सुषमा स्वराज की बेटी की सियासत में एंट्री

**नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को भाजपा दिल्ली राज्य कानूनी प्रकोष्ठ का सह-संयोजक नियुक्त किया है। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने राज्य इकाई में अपनी पहली नियुक्ति में कहा कि बांसुरी के नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। शुक्रवार को जारी पत्र में सचदेवा ने उम्मीद जताई कि वह भाजपा को मजबूत करेंगी। बांसुरी ने अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं को धन्यवाद दिया। एक ट्वीट में बांसुरी ने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली स्टेट लीगल सेल के राज्य सह-संयोजक के रूप में पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जीजेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी, विरेंद्र सचदेवा जी की आभारी हूं। बांसुरी, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील, अनुभवी भाजपा नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं।

### हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया

# राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पारित

**नईदिल्ली।** राहुल गांधी को लेकर सड़क से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। इस को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दसवां दिन था। लेकिन आज भी राज्यसभा में स्थिति सामान्य नहीं दिखी। विपक्ष सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने के मूड में था। दोपहर 2:00 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा और नारेबाजी चलता रहा। हंगामा और नारेबाजी के बीच ही जम्मू-कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट के साथ फाइनेंस विधायक को भी पारित कर दिया गया। इसे लोकसभा भी वापस भेज दिया गया है।

हंगामे के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश किया था। विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर विपक्षी नेताओं के नारेबाजी के बीच वोटिंग भी कराई गई। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुबह जो आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया मान लिया जाए। इसी बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को लौटाए जाने के साथ ही सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गयी।

सदस्य अडाणी समूह से जुड़े आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।

सदन ने चर्चा के बिना जम्मू-कश्मीर के सामान्य बजट, अनुदान की अनुपूरक मांगें और उससे संबंधित विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। इसके बाद सभापति की अनुमति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी सांसदों के साथ नजर आए।

भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाकर रखने की बात कहने वाली तृणमूल के सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित ऑफिस में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए। प्रसून बनर्जी और जरवार सरकार ने बैठक में टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया। विपक्ष की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में रणनीतिक रूप से अब कैसे आगे बढ़ा जाए। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय बाद कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की किसी बैठक में शामिल हुई।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन सभी का स्वागत करेगी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आए आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया। इसलिए, मैंने कल सभी को धन्यवाद दिया और मैं आज भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम उन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो हमारा समर्थन करते हैं।

### 17 पार्टियों ने बैठक में लिया हिस्सा

राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के विरोध में कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। तेलंगाना में कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी के चंद्रशेखर राव के

### तृणमूल सांसद भी विपक्ष की बैठक में हुए शामिल

# काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी नेता

**नई दिल्ली।** आपराधिक अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई है। हालांकि, इस मामले पर विपक्ष का विरोध तेज होता जा रहा है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के साथ कई और विपक्षी पार्टियां आ खड़ी हुई हैं। इसी क्रम में सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी विपक्षी सांसदों के साथ नजर आए।

नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति ने भी ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इसके अलावा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता भी काली शर्ट पहनकर पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी के मैं गांधी हूं सावरकर नहीं वाले बयान पर पहले ही उद्धव ठाकरे नाराजगी जता चुके हैं और बार-बार सावरकर का अपमान नहीं करने की हिदायत भी अपने एक बयान में दी है। बहरहाल, सामने आई जानकारी के अनुसार 17 विपक्षी दलों - आईएनसी, डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जम्मू-कश्मीर एनसी और शिवसेना (यूबीटी) ने बैठक में भाग लिया।

बताते चलें कि लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने राहुल गांधी को आयोग ठहराये जाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में किया गया यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य सैयद नासिर हुसैन और कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करते हुए कार्यस्थगन के नोटिस दिए। इन सबके बीच संसद की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामे की वजह से राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी।

# संसद का चल पाना अब पहले से ज्यादा मुश्किल

**नईदिल्ली।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने का असर अब संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है। सोमवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर हंगामा हो गया। हंगामे के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले से ही दोनों सदनों की कार्यवाही पिछले 11 दिनों में से एक दिन भी नहीं चल पाई है। अब राहुल की सदस्यता जाने के बाद जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। इससे लोकसभा की कार्यवाही चल पाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है।

बजट सत्र का दूसरा हिस्सा इसी माह की 13 मार्च को शुरू हुआ था। 24 मार्च तक एक दिन भी सामान्य तरीके से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई है। लोकसभा में अनुदान मांगें, सप्लीमेंट्री बजट, जम्मू-कश्मीर का बजट और शुक्रवार को फाइनेंस बिल पास हो गया है। इसके अलावा कोई भी काम लोकसभा में नहीं हुआ है। पूरे 11 दिन दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एक मंच पर नजर आ रहे हैं, इसका असर अब संसद की कार्यवाहीं पर पड़ने के आसार नजर आ रह है। ऐसी स्थिति में संसद के बचे हुए सत्र को चलाना मुश्किल नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। जबकि कुछ बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं। कुछ का उच्च सदन से पास होना बाकी है। अगर विपक्ष हंगामा जारी रखता है, तो रामनवमी के पहले दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि यह सत्र छह अप्रैल को खत्म होने जा रहा है।

सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस के सांसद आक्रामक रहेंगे। सोमवार को इसी रणनीति के तहत काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्ष के सदस्यों ने विरोध-प्रदर्शन किया। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास जुटे और अदाणी मुद्दे पर तख्तियां लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं संसद के बाहर भी कांग्रेस सड़क पर दिखेगी, देशव्यापी आंदोलन के साथ यूथ कांग्रेस संसद घेराव भी करेगी। हालांकि विपक्ष विरोध से अलग सरकार दोनों की सदनों को चलाने का प्रयास करेगी। सरकार लोकसभा में पांच विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

## वेस्टइंडीज और अफ्रीका के बीच हुए टी20 के सभी कीर्तिमान ध्वस्त

**सेंचुरियन।** क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां कोई रिकॉर्ड परमानेंट नहीं रहता और ना ही कोई भी चीज असंभव है। ताजा उदाहरण हमने वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टी-20 मुकाबले में भी देखा। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 259 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, यह लक्ष्य क्रिकेट के किताब में इतना आसान तो नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने अपने खेल से जबरदस्त धमाल मचाते हुए इस लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया था। बल्लेबाजी के लिए पिच काफी अनुकूल थी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इसका फायदा भी उठाया और 258 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वह भी 5 विकेट के नुकसान पर।

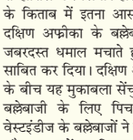

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने महज 46 गेंदों में 118 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसमें 11 छक्के और 10 चौके शामिल थे। चार्ल्स ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। रिकॉर्ड देखे तो वेस्टइंडीज के किसी प्लेयर का यह सबसे तेज शतक टी20 क्रिकेट में है। इतने बड़े लक्ष्य को सेट करने के बाद शायद ही वेस्टइंडीज की टीम ने यह सोचा हो कि उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरू से ही अपने लय में नजर आ रही थी। दक्षिण अफ्रीका के सलामी और अनुभवी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने धमाकेदार बल्लेबाजी से पावरप्ले में ही 102 रन बना डाले। इस मुकाबले में कुल 570 रन बने। यह किसी भी एक टी-20 मैच में सर्वाधिक है। इसमें वेस्टइंडीज की ओर से 22 छक्के लगे जबकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से 13 छक्के लगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स 127 अंक उछला निफ्टी 17 हजार के करीब

**नईदिल्ली।** यूरोपीय बाजार में उछाल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति तथा एसबीआई के शेयरों में वृद्धि के साथ स्टॉक मार्किट में सोमवार को तेजी दर्ज की गई और बाजार 100 से अधिक अंक चढ़कर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 126.76 अंक या 0.22 प्रतिशत चढ़कर 57,653.86 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 492.45 अंक या 0.85 प्रतिशत बढ़कर 58,019.55 पर पहुंच गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई निफ्टी 40.65 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 17 हजार के करीब 16,985.70 पर बंद हुआ। सेंसेक्स फर्मों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, सन फार्मा, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़त लेकर बंद हुए।

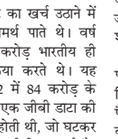

## दिवालिया हो चुके सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहकों को राहत

**नई दिल्ली।** एफडीआईसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक की 17 पूर्व शाखाएं सोमवार को फर्स्ट-सिटीजन बैंक के रूप में खुलेंगी। नियामक (फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि फर्स्ट सिटिजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) से सिलिकॉन वैली बैंक की सभी जमा और ऋण खरीदेगी। एफडीआईसी ने कहा कि उसने फर्स्ट-सिटीजंस बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी, रैले, उत्तरी कैरोलिना की ओर से सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक, नेशनल एसोसिएशन के सभी जमा और ऋणों की खरीदारी का समझौता किया है। एफडीआईसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक नेशनल एसोसिएशन की 17 पूर्व शाखाएं सोमवार 27 मार्च 2023 को फर्स्ट-सिटीजंस बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी के रूप में खुलेंगी।

## वनवेब उपग्रहों का प्रक्षेपण पीएम की मदद से गेमचेंजर साबित हुई

**नई दिल्ली।** उपग्रह दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वनवेब के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर हस्तक्षेप और इसरो रॉकेट उपलब्ध कराने में भारत सरकार के समर्थन ने रविवार को वनवेब के 36 उपग्रहों के अंतिम सेट के महत्वपूर्ण प्रक्षेपण का रास्ता साफ किया। लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार फर्म ने कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो एलएमवी 3 रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह कंपनी को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज देने की क्षमता प्रदान करेगा। दूरसंचार कारोबारी ने प्रक्षेपण के बाद ऑनलाइन बातचीत में मीडियाकर्मियों से कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षण को पहचाना और भारत में पूरे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को वनवेब को दो रॉकेट मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उनका यह फैसला हमारे लिए पासा पलटने वाला यानी गेम चेंजर साबित हुआ है।

## एसएंडपी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6 फीसदी पर रखा बरकरार

**नईदिल्ली।** साख निर्धारण करने वाली एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को छह प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। एजेंसी ने इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई। एशिया-प्रशांत के लिए त्रैमासिक आर्थिक जानकारी को अद्यतन करते हुए एसएंडपी ने कहा कि मुद्रास्फीति दर चालू वित्त की 6.8 प्रतिशत से नरम होकर 2023-24 में पांच प्रतिशत पर होगी। वहीं, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष (2022-23) में सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगा लेकिन 2023-24 में यह कम होकर छह प्रतिशत पर आ जाएगा। इसमें कहा गया, ''2024-2026 में भारत की औसत वृद्धि दर सात प्रतिशत होगी।''

# गरीब और वंचितों को भी मुख्यधारा से जोड़ रही है डिजिटल क्रांति

**अश्विनी वैष्णव**

कुछ साल पहले तक प्रौद्योगिकी सुलभ होना किसी के लिए बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी और यह केवल शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो इंटरनेट का खर्च उठाने में स्वयं को बिल्कुल असमर्थ पाते थे। वर्ष 2014 तक केवल 25 करोड़ भारतीय ही इंटरनेट का उपयोग किया करते थे। यह संख्या बढ़कर वर्ष 2022 में 84 करोड़ के आंकड़े को छू गई। पहले एक जीबी डाटा की कीमत करीब 300 रुपये होती थी, जो घटकर लगभग 13.5 रुपये प्रति जीबी रह गई है। इंटरनेट सस्ता हो जाने से लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ बड़ी आसानी से उठाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रौद्योगिकी को गरीबी के खिलाफ लड़ाई के एक अहम साधन में बदलने से लोगों को काफी लाभ हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। एआई, 5जी और क्वांटम प्रौद्योगिकी का चलन अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वे अब मुख्यधारा में शामिल होती जा रही हैं।

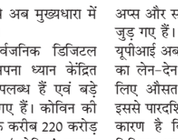

भारत ने ऐसे सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो सभी को उपलब्ध हैं एवं बड़े पैमाने पर सृजित किए गए हैं। कोविन की बदौलत भारत ने अब तक करीब 220 करोड़ खुराक दे दी है। आज 'कोविन' समस्त देशवासियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी सुलभ कराने का एक अभूतपूर्व उदाहरण बन गया है। आज पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर्स, छोटी-छोटी दुकानों से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक में डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्टिकर नजर आते हैं।

सार्वजनिक धन का उपयोग करके सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे बैंक, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और सबसे महत्वपूर्ण 120 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया यूपीआई अब हर साल 15 खरब डॉलर मूल्य का लेन-देन करता है। प्रत्येक लेन-देन के लिए औसत निपटान समय दो सेकंड है। इससे पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ी है। यही कारण है कि भारत का 'यूपीआई' अब डिजिटल भुगतान के लिए एक वैश्विक मानक बन गया है। लोगों के जीवन को आसान बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। 'फास्टैग' से अब वाहन राजमार्गों पर बिना रुके फर्राटे भरते हैं। 5जी का शुभारंभ होने के साथ ही प्रौद्योगिकी ने ऊंची छलांग लगाई है और 481 जिलों में 5जी कवरेज वाली एक लाख से भी अधिक साइटों को स्थापित किया जा चुका है। भारत आगामी तीन वर्षों में 4जी और 5जी प्रौद्योगिकी का निर्यातक बनने की दिशा में भी निरंतर काम कर रहा है।

अब भारत 'ओसीईएन (ओपन क्रेडिट एनैबलमेंट नेटवर्क)' विकसित कर रहा है, जो बैंकिंग प्रणाली को 'नकदी प्रवाह-आधारित ऋण व्यवस्था' में परिवर्तित करके देश भर में कर्जों की उपलब्धता काफी हद तक बढ़ा देगा। 'ओसीईएन' से लोगों को ऋण देने के लिए विभिन्न बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे कर्ज की लागत कम हो जाएगी। मॉर्गन स्टेनली के अनुमान के अनुसार, इसकी बदौलत कर्ज-जीडीपी अनुपात मौजूदा 57 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2031 तक 100 फीसदी हो जाएगा। डिजिटल और प्रौद्योगिकी-आधारित क्रांति आम नागरिकों के जीवन को सशक्त और रूपांतरित कर रही है। यह सबसे गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बना रही है और देश को युवा एवं प्रतिभाशाली पीढ़ी की रचनात्मक सोच के जरिये कुछ विशेष सृजित करने की क्षमता प्रदान कर रही है। इसी मॉडल को अब विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक्स हो, कृषि हो या रक्षा क्षेत्र। ऐसे प्लेटफॉर्म सृजित किए जा रहे हैं, जिन पर स्टार्ट-अप्स या किसी उद्यम का सक्रिय इको सिस्टम आगे चलकर सटीक समाधान विकसित कर सकता है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत अपने 'अमृत काल' में प्रवेश कर चुका है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी, निर्णायक नेतृत्व में भारत की जी-20 अध्यक्षता पथप्रदर्शक साबित होगी, और इस दौरान सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना को पूरी दुनिया के साथ साझा किया जाएगा।

# संयत भाषा का इस्तेमाल करें नेता

**आशुतोष चतुर्वेदी**

आजकल बिना सोचे समझे बोलने का रिवाज-सा चल गया है। कई बार नेता, चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के, अनर्गल बातें बोलते हैं। वे यह नहीं समझ रहे हैं कि यह सोशल मीडिया का दौर है, देश के किसी भी कोने में कही उनकी बात की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मामला सुर्खियों में है। उन्हें मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए सूरत की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनायी थी, जिसके आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सलाहकारों ने राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी, अन्यथा राहुल गांधी माफी मांग कर इस मामले से मुक्त हो सकते थे। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी सजा के खिलाफ तत्काल ऊपरी अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटाया गया। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पर की गयी अनर्गल टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। पवन खेड़ा तत्काल हरकत में आये और सुप्रीम कोर्ट चले गये, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गयी थी। विधि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मानहानि के ज्यादातर मामले अदालत में माफी मांगने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगर राहुल गांधी भी माफी मांग लेते, तो वे न तो दोषी ठहराये जाते और न ही उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त होती।

भले ही आज राहुल कह रहे हों- 'मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता,' जबकि सच यह है कि वे पहले कई बार माफी मांग चुके हैं। साल 2013 में राहुल गांधी ने अपनी ही यूपीए सरकार के एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। वह अध्यादेश उसी कानून को बदलने के लिए था, जिसके तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तब उन्होंने अध्यादेश को बकवास बताया था। साल 2018 में उन्होंने इस कृत्य के लिए माफी मांगी थी। फिर 2018 में राफेल मुद्दे पर फंसे राहुल ने 2020 में माफी मांगी थी। वर्ष 2018 में कहे गये 'चौकीदार चोर है' वाले मामले में भी 2019 में माफी मांग कर वे उससे मुक्त हो गये थे। कई अन्य नेताओं ने भी अदालत में माफी मांग कर खुद को बचाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने 2015 में 10 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था। तीन साल बाद केजरीवाल की ओर से लिखित माफी के बाद मामला समाप्त हो गया था। केजरीवाल अन्य मामलों में भी नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से माफी मांग चुके हैं। इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो शायद उन्हें सजा न मिलती और न ही उनकी लोक सभा की सदस्यता जाती।

यह सभी स्वीकार करते हैं कि इतने वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद राहुल गांधी नपा-तुला नहीं बोलते हैं। कई बार तो उनकी बातों के सिरे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा- यह मेरी तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे अयोग्य ठहराएं, मारें-पीटें, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। मुझे अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे, क्योंकि मैं सदन में अदानी मामले पर अपना अगला भाषण देने वाला था। मैंने उनकी आंखों में यह डर देखा है। उन्होंने एक पत्रकार की भी बिलावजह लानत-मलानत कर दी, जो उचित नहीं थी। मैंने पिछले सप्ताह के अपने लेख में कहा था कि नियम-कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आप भले ही कितने खास हों, आपको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अपने देश के किसी कोने में किसी सांसद, मंत्री अथवा सेलिब्रिटी को हाथ लगाने पर पूरे तंत्र पर हल्ला बोल दिया जाता है। यह बात कोई छुपी हुई नहीं है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। नेता-अभिनेता क्या, उनके सगे-संबंधी भी अपने को कानून से ऊपर मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों की जो स्थिति है, उसने विपक्ष को बेहद कमजोर कर दिया है। अब हालत यह है कि 1885 में स्थापित कांग्रेस आज अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रही है। इस साल अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ऊहापोह की स्थिति में है।

# राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा?

**अजय सेठिया**

विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जाट जाति के सतीश पूनिया को हटा कर ब्राह्मण जाति के जोशी को अध्यक्ष बनाने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान यह कहना थोड़ा मुश्किल है। राजस्थान में 89 फीसदी आबादी हिंदू हैं, 9 फीसदी मुस्लिम और 2 फीसदी अन्य धर्मों के लोग हैं। हिन्दुओं में गैर जाट पिछड़ी जातियों की जनसंख्या लगभग 25 प्रतिशत, सभी अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 17 फीसदी है, तो अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित आबादी 13 फीसदी है। जाटों की कुल आबादी 10 से 11 फीसदी, राजपूतों की आबादी 7 से 8 फीसदी, ब्राह्मण, मीणा और गुर्जर की आबादी लगभग 6-7 फीसदी है7 वैश्य आबादी लगभग 4 प्रतिशत है। बाकी अन्य जातियां हैं। तो जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश के नेता पद पर पहला हक गैर जाट पिछड़ी जातियों का बनता है। उनके बाद अनूसूचित जाति या जनजाति के नेता का बनता है। अब तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जाटों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था, क्योंकि राजस्थान के जाट राजनीतिक तौर पर बहुत मुखर हैं7 इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में उभर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जाटों की पार्टी ही माना जाता है, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक मजबूत जाट नेता के रूप में उभर रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान के तीनों बड़े दलों की कमान अब तक जाटों के कब्जे में थी।

भाजपा ने अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट को हटा कर ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उसका कारण जाट मतदाताओं का तीनों दलों में बिखराव है। इसके अलावा जाट मतदाता किसी पार्टी के पीछे नहीं रहते और अपने समाज के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं, भले ही वह किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। जाटों की तरह ब्राह्मण मतदाता भी भाजपा के उभार से पहले ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहता आया है और अब भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति के कारण उसकी तरफ झुका है। उनके मुकाबले वैश्य और राजपूत मतदाता का रुझान भाजपा के साथ रहा है। एक जमाना था, जब राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। राजस्थान की पहली विधानसभा में 60 ब्राह्मण जीत कर आए थे। वैसे उस जमाने में, जब बाकी जातियां राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं थीं, पूरे देश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। कांग्रेस ने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 41 प्रतिशत टिकट ब्राह्मणों को दिए थे, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 12 प्रतिशत थी बाद में जैसे जैसे दूसरी जातियों में राजनीतिक चेतना आई, स्थिति बदलती चली गई।

फिलहाल राजस्थान विधानसभा के 200 के सदन में सिर्फ 17 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि जाट विधायक 31 है, और अक्सर हर विधानसभा में लगभग 30 जाट विधायक चुनकर आ रहे हैं। जो 200 विधायकों की संख्या का 15 प्रतिशत है। लेकिन इनमें ज्यादा संख्या कांग्रेस से चुने गए जाट विधायकों की ही रही है। राजस्थान में राजपूतों का राजनीतिक प्रभाव भी ज्यादा रहा है। उनकी आबादी 9 प्रतिशत है, लेकिन वे 50 से अधिक सीटों पर असर डालते हैं और 25-26 सीटों पर जीत कर आते हैं7 पूर्वी राजस्थान में मीना और गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है7 मीना 40 सीटों पर अच्छी संख्या में हैं, तो गुर्जर 30 सीटों पर। लेकिन इन सीटों के बाहर इनकी संख्या बहुत कम हैं। जाट भले ही 30-32 जीत कर आते हैं, लेकिन वे भी 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं।हालांकि उनका स्पष्ट रुझान अपनी जाति के जिताऊ उम्मीदवार के प्रति होता है, भले ही किसी भी पार्टी का हो। इसलिए राजस्थान में किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए गैर जाट ओबीसी वोट को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वह जाटों की बहू हैं, राजपूतों की बेटी हैं और गुर्जरो की समधिन हैं। इन तीनों जातियों की राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका रहती है। हालांकि राजपूत और जाट परस्पर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ यह समीकरण फिट बैठता है।

राजस्थान में हमेशा से जातिवाद रहा है, लेकिन सत्तर के दशक तक राजनीति में ब्राह्मण हावी रहे, उसके बाद जब अन्य जातियों में राजनीतिक चेतना आई, तब से ब्राह्मण हाशिए पर चले जाते रहे। इसके बाद एक जमाना वह भी रहा था जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वोट बैंक को उतना प्रभावित नहीं करता था, तब कांग्रेस और भाजपा दोनों ब्राह्मण अध्यक्ष बना दिया करते थे। कांग्रेस में जयनारायण व्यास, गिरधारी लाल व्यास, गिरिजा व्यास, बीडी कल्ला और सीपी जोशी सहित कई प्रदेशाध्यक्ष रहे। भाजपा में भी उनसे पहले महेश चंद्र शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा, और अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष रहे। हालांकि 1980 के बाद दोनों पार्टियों ने प्रदेश में ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए, लेकिन सच यह है कि 1980 के बाद से राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव घटता चला गया। उनकी जगह पर ओबीसी, जाट, मीना, गुर्जर, एससी-एसटी प्रभावी होते चले गए। भैरोसिंह शेखावत अपने बूते कभी भाजपा को बहुमत नहीं दिला सके, जबकि राजपूत, जाट, गुर्जर के समीकरण वाली वसुंधरा राजे भाजपा को भारी बहुमत में ले आई। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी को पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटों पर जीत मिल गई। इस बार चुनाव से पहले जातीय सम्मेलनों का शुरू होना बता रहा है कि चुनाव में जातीय राजनीति फिर से ज्यादा हावी रहेगी7 पिछले दो सप्ताह पर नजर डालें तो जाट और ब्राह्मण समाज ने बड़ी सभाएं कर अपनी ताकत दिखाई है। 5 मार्च को जहां जयपुर में जाट महाकुंभ हुआ तो वहीं 19 मार्च को जयपुर में ही ब्राह्मण महापंचायत हुई7 अब 2 अप्रैल को राजपूतों की बड़ी पंचायत भी जयपुर में होने जा रही है7 भाजपा क्योंकि केंद्र में सत्ता में है, तो उसके पास जातियों को साधने के ज्यादा संसाधन मौजूद हैं। उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा ने अपनी तरफ से सबको सत्ता बांटने का काम किया है। केंद्र में एक राजपूत गजेंद्र सिंह शेखावत, एक एससी अर्जुन राम मेघवाल, एक जाट कैशाल चौधरी और एक यादव भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया हुआ है। वैसे भूपेंद्र यादव मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं। इसके अलावा उड़ीसा से राज्यसभा में गए राजस्थान के अश्विनी वैष्णव को ब्राह्मण मंत्री कह सकते हैं। लेकिन उनकी जाति राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला वैश्य वर्ग से आते हैं। जबकि जाट के नाते जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया है।

भाजपा से संकेत यह भी आ रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्यसभा में लाकर, फिर उन्हें रेल मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी उन्हें राजस्थान के भावी नेता के रूप में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुई राजस्थान की ब्राह्मण महापंचायत में रेलमंत्री अश्निनी वैष्णव भी पहुंचे हुए थे। आमतौर पर राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रहने वाले अश्विनी वैष्णव इस पंचायत में नारे लगाते दिखे। उनका ये अवतार राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उनका इस तरह पंचायत में पहुंचना कई तरह के सियासी संकेत देता है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ओबीसी कार्ड भी चला रहे हैं। वैसे ओबीसी राजनीति के जमाने में देश के सबसे बड़ी ओबीसी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में राजपूत मुख्यमंत्री है और सिर्फ 3 प्रतिशत ब्राह्मण आबादी वाले असम में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। राजस्थान की बात कुछ और है, वहां चेहरा दिखा कर जातीय राजनीति को साधना बहुत जरूरी है। राजस्थान के जातीय समीकरणों की वास्तविकता को नजरअंदाज करके नरेंद्र मोदी राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्य भूमिका से किनारे करने के कई प्रयास कर चुके हैं और अब तक विफल रहे हैं। शुरू में उन्होंने ओम प्रकाश माथुर का नाम भावी मुख्यमंत्री के रूप में चलवाया, फिर कुछ दिन गजेन्द्र शेखावत का नाम चलवाया, बीच बीच में ओम बिड़ला भी अपना नाम चलवाते रहे, लेकिन कुछ नहीं चला। अब अश्निनी वैष्णव ने अपना नाम चलवाया हुआ है। राजस्थान में मोदी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ने की बातें भी चल रही हैं, लेकिन ये सारे प्रयास राजस्थान की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं।

दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो उसका जातीय समीकरण बहुत मजबूत है। पिछड़ी जाति के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो जाट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, ब्राह्मण विधानसभा अध्यक्ष है, तो सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं। इसके अलावा 9 प्रतिशत मुस्लिम और 17 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के भी कांग्रेस के परम्परागत वोटर हैं। कुल मिलाकर यह लग रहा है कि गहलोत के मजबूत आधार को काटने के लिए मोदी को फिर से जाट, राजपूत और गुर्जर के संयुक्त समीकरण वाली वसुंधरा राजे को ही आगे करना पड़ेगा। ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की जीत में सहायक सिद्ध हो सकता है।

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

# याज्ञवल्क्यापनिषद् (भाग-05)

**गतांक से आगे...**

वैसे पुत्र भी कष्ट देने वाला ही होता है; क्योंकि पुत्र न होने पर माता-पिता को बहुत क्लेश होता है। यदि किसी प्रकार से (पुत्र) हो भी जाता है, तो उसे ग्रह, रोग आदि हो जाते हैं या फिर बालक ही नालायक हो जाता है। वह यज्ञोपवीत हो जाने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है और यदि पढ़-लिख जाये, तो विवाह होना दुष्कर हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जवान लड़के का पर नारी से बुरा सम्पर्क न हो जाये आदि भय बना रहता है या फिर यदि विवाह हो जाये, तो बालकों की इतनी संख्या हो जाती है कि परिवार का भरण-पोषण भी कठिन हो जाता है। इस तरह से पुत्र से होने वाले दु:खों की कोई गणना नहीं। इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि सेठ लोगों के बच्चे ही नहीं होते और यदि होते भी हैं, तो मर जाते हैं आदि-आदि। (अत: इन समस्त दु:खों की कारण भूत स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए या विवाह ही न करे)न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः । यति को हाथ, पैर, आँखों और वाणी का चंचल नहीं होना चाहिए अर्थात् उसे पूर्ण जितेन्द्रिय होना चाहिए। तभी वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकता है।

शत्रु एवं सांसारिक बन्धनों से युक्त शरीर में जो एक भाव से देखने वाला ज्ञानशील यति होता है, उसे किसी पर भी क्रोध नहीं आता। जिस प्रकार कि व्यक्ति को अपने हाथ-पैर आदि अंगों पर क्रोध नहीं आता। क्रोध करने वाले आदमी से पूछना चाहिए कि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो; जो समस्त वस्तुओं का मूल कारण है। साथ ही जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का बलवान् बैरी है ।

प्रदान करने वाले एवं दोषों का बोध कराने वाले कोप को बारम्बार नमन-वंदन है ॥ 30 ॥ यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी । प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्सुषुप्तिं याति योगिराट् ॥ 31 ॥ जहाँ (जब) सामान्य जन शयन करते हैं, वहाँ (तब) संयमी पुरुष जागता है (संयमी पुरुष पूर्ण सावधान रहता है तथा जब अन्य सामान्य जन जागते हैं, तब योगी पुरुष सुषुप्ति का आश्रय प्राप्त कर लेता है यति को यही भावना करनी चाहिए कि मैं इस संसार में चित्स्वरूप ही हूँ। अखण्ड ब्रह्माण्ड चिन्मय है तथा सभी कुछ चिद्रूप ही है। मैं भी चिद् ही हूँ एवं सम्पूर्ण सृष्टि चिद्रूप ही है ॥ 32 ॥ यतीनां तदुपादेयं पारहंस्यं परं पदम् । नातः परतरं किंचिद्विद्यते मुनिपुङ्गव इत्युपनिषत् ॥ 33 मुनिश्रेष्ठ ! परमहंस का परम श्रेष्ठ पद मोक्ष ही यतियों के लिए उपादेय (अर्थात् आवश्यक वस्तु) है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही सर्वोत्कृष्ट है।

# स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 की क्रांति में दिया योगदान

**रितिका कमठान**

भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में पहचाने जाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर जोर दिया था। हिंदी को राष्ट्र भाषा के तौर पर उन्होंने ही स्वीकार किया था।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी क्रांति की शुरुआत की। घर से निकलने के बाद वो अंग्रेजों के खिलाफ काफी प्रखर होकर बोलने लगे। उन्होंने पाया कि लोगों में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है। इसके बाद उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, हाजी मुल्ला खां, बाला साहब आदि को एकजुट कर देश की आजादी और अंग्रेजों के खिलाफ तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले साधु संतों को अपने साथ लिया जो आजादी के लिए जनता को प्रेरित कर सके।

उन्होंने 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान दिया। हालांकि ये क्रांति अधिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद उन्होंने जनता को समझाया कि वर्षों की गुलामी को एक संघर्ष में हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आजादी की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, जिसके बल पर लोगों का हौसला बना रहा। उन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। गुड़ी पड़वा के दिन रखी गई नींव के आधार पर तय किया गया कि आर्य समाज का मुख्य धर्म, मानव धर्म था। आर्य समाज का मुख्य आधार परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान था। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक, शारीरिक एवम सामाजिक उन्नति प्रदान करना था। आर्य समाज की इन विशेषताओं ने कई विद्वानों को प्रेरित किया। इसके अलावा आर्य समाज में मूर्ति पूजा, पशुओं की बलि देना, मंदिरों में चढ़ावा देना, जाति विवाह, मांस का सेवन, महिलाओं के प्रति असमानता की भावना को भी मिटाने की कोशिश की।

उन्होंने समाज के प्रति उत्तरदायी होते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा का विरोध किया। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरुक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि बाल विवाह से मनुष्य निर्बल बनता है, जिससे समय से पूर्व मृत्यु प्राप्त होती है। उन्होंने अमानवीय सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने देश में विधवा पुनर्विवाह की बात की और इसके प्रति लोगों को जागरुक किया। विधवा स्त्रियों के संघर्षपूर्ण जीवन की निंदा करते हुए उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। उन्होंने नारी शक्ति का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि नारी शिक्षा समाज का आधार है, इसलिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। उन्होंने एकता का संदेश भी दिया। उन्होंने सभी धर्मों और उसके अनुयायियों को एकजुट होने का संदेश दिया। उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का लाभ तीसरे को हो जाता है, जिसके लिए जरुरी है कि आपसी भेदों को दूर किया जाए। उन्होंने एकजुटता का संदेश देने वाली कई सभाओं का नेतृत्व किया मगर इस सपने को वो साकार ना कर सके।

# द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों में संतुलन की कवायद

**शोभना जैन**

इसी सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में राजनयिक चर्चाओं के बीच किशिदा के गोलगप्पों का स्वाद लेते, आम का पना और लस्सी की चुस्कियां लेते वीडियो खासे सुर्खियों में रहे। दरअसल भारत-जापान संबंधों के लिए तो जापान के पीएम की यह यात्रा अहम है ही, भारत-प्रशांत साझीदारी को गति देने के साथ ही जिस तरह से किशिदा ने भारत यात्रा के फौरन बाद उस वक्त यूक्रेन की यात्रा की जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मास्को में यूक्रेन मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूरेशिया की तरफ से रूस के साथ खड़े रहने का स्टैंड दोहरा रहे थे, वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत यूक्रेन मुद्दे पर तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है। किशिदा जी-7 के एकमात्र ऐसे शासनाध्यक्ष हैं जिसने अब तक स्वयं यूक्रेन का दौरा कर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन मुद्दे पर एकजुटता व्यक्त नहीं की थी। ऐसे में निश्चय ही इस यात्रा को दोनों देशों के बीच कुछ विषम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर असहमति होने के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को गति देते हुए, कुछ मुद्दों पर एक-दूसरे के राष्ट्रीय हितों को समझते हुए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश माना जा सकता है।

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच इस बार का भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझबूझ बढ़ रही है। भारत और जापान अपने संबंधों में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व लगातार एक-दूसरे के संपर्क में रहता है। जापान सरकार के ऋण से बनने वाली मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना हालांकि अभी अटकी हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच आधारभूत क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

साथ ही अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यूक्रेन जैसे उलझे मौजूदा हालात के चलते यह यात्रा खास अहमियत रखती है। क्वाड समूह अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत करने और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। यह साल भारत और जापान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश अपने पड़ोसी चीन की आक्रामकता को लेकर समान रूप से चिंतित हैं। भारत के पास जी-20 की अध्यक्षता है और जापान के पास जी-7 की अध्यक्षता है। भारत के जी-20 का अध्यक्ष और जापान के जी-7 का अध्यक्ष होने के नाते दोनों की ही साझी सोच और प्रयास है कि वैश्विक मुद्दों पर खास तौर पर गरीब देशों को समान रूप से साथ लाया जाए। हालांकि यूक्रेन को लेकर भारत और जापान दोनों का अलग-अलग रुख है। जापान इस मसले पर अमेरिका नीत गठबंधन के साथ खुल कर खड़ा है। यह गठबंधन रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। एक पूर्व राजनयिक के अनुसार आज दुनिया अलग-अलग खेमों मे बंट रही है, ऐसे में भारत और जापान दोनों का ही प्रयास है कि जी-7 और जी-20 की अपनी-अपनी अध्यक्षता के दौरान दोनों साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास कदम उठाएं, उसे एक नई दिशा देने का प्रयास करें। इस बार भारत आकर फुमियो किशिदा ने जी-7 के एजेंडे को जी-20 के एजेंडे के साथ समन्वित करने की जो कोशिश की है, वह भी इस बात को रेखांकित करता है कि चाहे हमारे बीच यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर मतभेद भी हों, उसके बावजूद हम अपने सामरिक संबंधों को कमजोर नहीं होने देना चाह रहे हैं। गौरतब है कि पीएम मोदी इसी वर्ष मई में हिरोशिमा में विकसित देशों के जी-7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं।

किशिदा की इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस बार उनके एजेंडे में 'मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र'है। चीन का आक्रामक तेवर जिस तरह भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में दिखा, इसी पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन द्वारा आक्रामक मंसूबों को लेकर दिए गए संदेश के चलते ही एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने के लिए भारत सहित क्वाड समूह के बीच यह एकजुटता आई है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आज एक ही भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है और उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलाकर बना क्वाड भी इस बात को रेखांकित करता है कि किस तरह से एक समान सोच रखने वाले लोकतांत्रिक देश आपस में मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं। इसलिए जब चीन जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या भारत के साथ आक्रामक रुख दिखाता है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि इन देशों की जो क्षमताएं हैं, वो अब एक साथ मिल चीन को टक्कर देने की तैयारी कर रही हैं।

**गांधी आज**

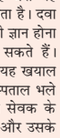



# इलाज(भाग-01)

शरीर में अस्वस्थता मालूम होने पर रोग को रोकनेवाले इलाज पर अमल करना, पहली सीढ़ी है। इन इलाजों पर ठीक अमल हो तो रोग बहुत करके स्वाभाविक रूप से ही अच्छे हो जाते हैं। दवाइयाँ अधिकतर तो निकम्मी और हानिकर भी होती हैं। आहार-विहार की भूलों को दूर किए बिना सिर्फ हवा-पानी के सुधार से रोग दूर करने की इच्छा करना शरीर को साफ पानी से धोकर मैले गम से पोंछने जैसा है। और इन दोनों को सुधारे बिना दवा से आराम होने की कामना करना ऐसा है जैसे यह मानना कि मैला कपड़ा काला रंग लेने से साफ हो जाता है। दवा के अलावा दूसरे वैज्ञानिक इलाज हैं जिनका हरएक की ज्ञान होना चाहिए। आसानी से और बिना खर्च के किए जा सकते हैं। हरएक गाँव में दवाखाना या अस्पताल होना चाहिए, यह खयाल गलत है। अनेक गाँवों के बीच एक दवाखाना या अस्पताल भले ही हो। गाँव के दवाखाने के मानी आमतौर से ग्राम सेवक के उपचार होना चाहिए। सबसे अच्छा उपचार है उपवास और उसके साथ कटिस्नान तथा सूर्यस्नान इसकी उपयुक्त विधि का ज्ञान स्वयंसेवक को प्राप्त कर लेना चाहिए । इसके अलावा भीगी मिट्टी की पट्टी बहुतेरे रोगों और बुखारों का इलाज कही जा सकती है। बुखार तेज चढ़ा हो, सिर दुखता हो, पेट या पेडू में दर्द हो भीतरी चोट या दूसरे कारणों से कहीं सूजन आई हो, नकसीर फूटी हो, खसरा, खाज इत्यादि चर्मरोग हुए हों, कब्ज रहता हो, अच्छी द न आती हो. जहरीले जंतु ने डंक मारा हो इन सबमें कंकड़ी की बारीक मिट्टी भिगोकर उसकी पट्टी दर्द-तकलीफ की जगह बाँधना और एक पट्टी या लेप सूख जाने पर दूसरा बाँधना अकसीर और प्राकृतिक इलाज है। **क्रमशः...**

## संक्षिप्त समाचार

### राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन 28 मार्च को रहेंगे बिलासपुर प्रवास पर

**बिलासपुर।** राज्यपाल महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन 28 मार्च को बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे। वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल 28 मार्च को सवेरे 10.10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सवेरे 10.40 बजे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय स्थित हेलीपेड पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे सवेरे 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में इंडियन रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रम और विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात हेलीकॉप्टर द्वारा वे दोपहर 1.35 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

### लेखन सामग्री की खरीदी हेतु निविदा 10 अप्रैल तक

**बिलासपुर।** कलेक्टर कार्यालय, स्टेशनरी शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यालयीन उपयोग संबंधी लेखन सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय करने हेतु न्यूनतम दर निर्धारण करने स्थानीय विक्रेताओं से 10 अप्रैल 2023 दोपहर 3 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा के संबंध में अधिक जानकारी कलेक्टर कार्यालय के स्टेशनरी शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।

### तार मिस्त्री परीक्षा हेतु आवेदन 30 अप्रैल तक

**बिलासपुर।** संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) द्वारा तार मिस्त्री परीक्षा जुलाई माह में आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता कार्यालय, कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक बिलासपुर, प्रथम तल यूडीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग, होमगार्ड कैम्पस के पास कुदुदण्ड से प्राप्त कर सकते हैं।

### बिजली की नई दरों की घोषणा आज

**रायपुर।** प्रदेश में एक बार फिर बिजली की दर संशोधित होने जा रही है। छग राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकारी 28 मार्च को बिजली की नई दर जारी करेंगे। आयोग के अधिकारियों ने इस सत्र बिजली दर में उपभोक्ताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं। आपको बात दें कि पावर कंपनी ने आयोग को बिजली दर बढ़ाने का प्रपोजल भेजा था। दर बढ़ाने के पीछे पावर कंपनी ने कारण बताया था कि पूर्व सालों नुकसान की भरपाई हो सके। पावर कंपनी के प्रपोजल के बाद छग राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों ने आमसभा बुलाई। आमसभा में उपभोक्ताओं ने दर ना बढ़ाने की अपील की। उपभोक्ताओं की अपील सुनने के बाद आयोग के अधिकारियों ने नई दर निर्धारित की है। इसे मंगलवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

### अटल बिहारी वाजपेयी विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल हरिचंदन

**बिलासपुर।** राज्यपाल महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन 28 मार्च को बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे। वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल 28 मार्च को सवेरे 10.10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सवेरे 10.40 बजे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय स्थित हेलीपेड पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे सवेरे 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में इंडियन रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रम और विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात हेलीकॉप्टर द्वारा वे दोपहर 1.35 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

### विभिन्न गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा

**बिलासपुर।** रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 5 गाड़ियों में एक-एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा की उपलब्धता से इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे। विवरण इस प्रकार है - गाड़ी संख्या 08212 बिलासपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा बिलासपुर से 1 अप्रैल से 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 18239/18240 कोरबा-इतवारी-बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा कोरबा से 1 अप्रैल से 30 जून तक तथा इतवारी से 2 अप्रैल से 1 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 12856/12855 इतवारी-बिलासपुर-इतवारी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा 2 अप्रैल से 1 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी।

### नकली इंजन आयल बेचते संचालक गिरफ्तार

**रायपुर।** राजधानी रायपुर में नकली इंजन आयल का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौदहापारा पुलिस ने एक ऐसे ही शिव शक्ति लुब्रीकेंट के संचालक को नामी कंपनी का लेबल, स्टीकर लगाकर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। हीरो मोटोकार्प के अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर संजय जादवानी ने मौदहापारा पुलिस थाने में शिकायत की थी, कि देवपुरी स्थित शिव शक्ति लुब्रीकेंट के संचालक रोहित पिंजानी हीरो मोटोकार्प कंपनी के नकली इंजन आयल बेच रहा है।

# खुशहाली और समृद्धि के लिए किए जा रहे लगातार कार्य-मुख्यमंत्री

## न्याय योजनाओं के जरिए किसान, पशुपालक एवं मजदूरों की जेब में जा रहा पैसा

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अन्नदाता किसान संपन्न एवं खुशहाल रहें, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। न्याय योजनाओं के जरिए किसान, पशुपालक एवं मजदूरों की जेब में पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का दायरा बढ़ाते हुए 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है, इससे किसानों में खुशी का माहौल है। अन्नदाता किसान खुश होंगे तो समझिए भगवान खुश हैं। श्री बघेल राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड में कंवर महोत्सव एवं किसान महासम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 105 करोड़ 71 हजार रूपए की लागत के 19 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। जिसमें 8 करोड़ 66 लाख 39 हजार रूपए की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 96 करोड़ 34 लाख 32 हजार रूपए की लागत के 13 कार्यों का भूमिपूजन शामिल हैं। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के 165 हितग्राहियों को 2 करोड़ रूपए 56 लाख 40 हजार रूपए की सामग्री, वन अधिकार पट्टा, सामाजिक एवं अहाता निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश तथा प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कंवर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी को नवरात्रि एवं रमजान पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने पर किसानों ने उत्सव मनाया है। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों की संख्या एवं रकबा बढ़ा है। पहले 55 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, जो अब बढ़कर 107 लाख मिट्रिक टन हो गया है। राजनांदगांव जिले में किसानों की संख्या एवं रकबे में ढाई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। किसान खेती-किसानी के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपना रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथे किस्त की राशि किसानों को दे दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से नये जिले के गठन के बाद विकास कार्यों में गति आयी है। बजट सत्र के दौरान सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए कोटवार, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना नगरीय क्षेत्रों में भी प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 278 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गांव में ही युवाओं के लिए रीपा केन्द्रों में बिजली, पानी, शेड, एप्रोज रोड एवं अन्य व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी-मार्ट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की बिक्री की जा रही हैं। जनसामान्य को सस्ती कीमत पर दवाई उपलब्ध कराने के लिए धन्वंतरी मेडिकल स्टोर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के निःशुल्क ईलाज के लिए मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिीनिक योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एवं युवा मितान क्लब जैसी योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के साथ ही प्राकृतिक गोबर पेंट बनाया जा रहा है। जिससे शासकीय भवन तथा स्कूल भवन की पोताई की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 25 हजार रूपए से राशि बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के रोटी एवं पगड़ी को मान-सम्मान दिया है। प्रदेश के मुखिया ने अन्नदाता किसानों की कर्जमाफी की है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री नवाज खान ने कहा कि देश भर में अभी भूपेश मॉडल भरोसे मॉडल की चर्चा है।

### मुख्यमंत्री आज करेंगे फिल्मी कलाकारों को सम्मानित

**रायपुर।** गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र राजा गुरु बालक दास का 163वां बलिदान दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहीद स्मारक भवन में भंडारी, साटीदार समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया करेंगे। विशेष अतिथि विधायक सत्यनारायण शर्मा, रविवि कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा और मैत्रस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. केपी यादव होंगे। आयोजन समिति की संरक्षक शकुन डहरिया, अध्यक्ष केपी खंडे और प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि यह आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी तथा राजश्री सद्भावना समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यहां शौर्य प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा दल प्रमुखों के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रहे बलिदानी राजगुरु बालकदास फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

# कांग्रेस व राहुल को संविधान का सम्मान करना चाहिए -चंदेल

**रायपुर।** छ.ग. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया है। पूरा ओबीसी समाज आने वाले समय में इस अपमान का बदला लेगी। उन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी व उनके नेता राहुल गांधी को देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए। राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है कांग्रेस नेताओं की ये कोई पहली घटना नहीं है। संपूर्ण समाज व देश के कानून से कोई ऊपर नहीं है। उन्होने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी माँगनी पड़ी थी, फिर चैकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने एतराज जताया। इस नारे पर जनता जनार्दन की अदालत ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कांग्रेस को मुँह की खानी, पड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा, राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफी माँगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार

ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुँचाई, सूरत कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है। परंतु राहुल व कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े व निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा। छ.ग. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यलयों पर हमला करना असंवैधानिक है एवं निंदनीय है। शासन एवं पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर एकतरफा कार्यवाही की जा रही है जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा निर्देशित है।

# पारंपरिक लोक संगीत के साथ कुदरगढ़ महोत्सव का आगाज

**रायपुर।** सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी के धाम में तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का रविवार देर शाम लोक पारंपरिक गीतों के साथ आगाज हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कुदरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा अलग-अलग विधाओं में प्रस्तुत सुरमयी गीत-संगीत ने समां बांध दिया। महोत्सव में पारंपरिक लोक संगीत की धुनों के अलावा क्लासिकल डांस और भजन पर लोग झूमते रहे। संसदीय सचिव श्री परसनाथ राजवाड़े ने शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े ने अंचल के लोगों को चैत्र नवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉ. टेकाम ने इस मौके पर सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू बोर्ड के सदस्य श्री इस्माइल खान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश राजवाड़े, श्रीमती भगवती राजवाड़े, डीडीसी, बीडीसी, जनप्रतिनिधि गण, कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, एसडीसीएल महाप्रबंधक श्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम, कुदरगढ़ मेला समिति के अध्यक्ष श्री भुवन भास्कर प्रताप सिंह, ट्रस्ट के सदस्य, नागरिक गण, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। महोत्सव के पहले दिन नृत्यांगना डॉ. पूर्णाश्री राउत ने ओडिसी डांस, नन्हा सितारा ओम अग्रहरि ने प्रस्तुती दी। इसी तरह नासिर खान ने सूफी गायन, बीजीएम म्यूजिकल ग्रुप, भजन सम्राट दिलीप षडंगी ने आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना गायन की प्रस्तुति दी। महोत्सव में राज्य के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने पारंपरिक लोक-संगीत के माध्यम से समां बांधा।

# महिला शिखर सम्मान से सम्मानित हुई महिलाएं

**रायपुर।** वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छ.ग. एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छ.ग. द्वारा 26 मार्च 2023 को सायं वृन्दावन हॉल, सिविल लाईन्स, रायपुर में प्रदेश की विभिन्न विधा की 28 ख्यातिलब्ध विप्र महिला शक्तियों को नवरात्रि के अवसर पर महिला शिखर सम्मान से स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवम् बुके प्रदान कर सम्मानित किया गया. प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द क्षोझा ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथिगण श्रीमती अनिता शर्मा- विधायक धरसीवां, श्रीमती दीसि प्रमोद दुबे- वरिष्ठ समाजसेवी, श्रीमती सरिता आकाश दुबे- पार्षद ब्राम्हणपारा एवं श्रीमती सरिता तिवारी- प्राचार्य सोरिद रहीं. छत्तीसगढ़ के सभी पांच संभागों से सम्मानित होने वाली महिलाओं के नाम एवम् कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैं - 1. कु. अराधिता आर. विल्ही-शिक्षा, 2. श्रीमती आयुषी तिवारी- साहित्य एवम् शिक्षा, 3. डॉ. निहारबाला बाजपेयी-चिकित्सा, 4. डॉ. पलक शर्मा- चिकित्सा, 5. श्रीमती स्नेहलता तिवारी- समाज सेवा, 6. श्रीमती डी. अनिता राव- समाज सेवा, 7. श्रीमती सरोज दुबे विद्या- साहित्य, 8. डॉ. रिचा

ठाकुर- नृत्य कला एवम् शिक्षा, 9. श्रीमती सृष्टि शर्मा- शिक्षा एवम् साहित्य, 10. श्रीमती सीमा शर्मा-अभिनय एवं संचार,11. श्रीमती सुधारानी शर्मा- शिक्षा एवम् साहित्य, 12. डॉ. विभाषा मिश्रा-शिक्षा एवम् साहित्य, 13. श्रीमती मन्शा शुक्ला- शिक्षा एवं साहित्य, 14. श्रीमती राजलक्ष्मी पाण्डेय- साहित्य लेखन, 15. श्रीमती गार्गी पाण्डेय- न्याय एवं समाज सेवा, 16. डॉ. श्वेता बोहरा-शिक्षा. 17. रिचा द्विवेदी- समाज सेवा, 18. डॉ. मनीषा त्रिपाठी- शिक्षा, 19. श्रीमती शशि दुबे- शिक्षा एवं समाज सेवा, 20. श्रीमती मधु तिवारी- शिक्षा एवं साहित्य, 21. श्रीमती लक्ष्मी राव- महिला उत्थान एवम नशा मुक्ति, 22. वीणा मिश्रा - समाज सेवा, 23. प्रीति शुक्ला- समाज सेवा, 24. तुलसी तिवारी- समाज सेवा, 25. सविता शर्मा- समाज सेवा, 26. बी. शैलजा- समाज सेवा, 27. डॉ. प्रीति सतपथी- शिक्षा एवम् समाजसेवा.28. श्रीमती जागृति उपाध्याय- वित्तीय सेवा. सम्मानित होने वाली महिलायें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, रायगढ़, बेमेतरा, मुंगेली आदि सुदूर क्षेत्रों से पहुंची थीं.

कार्यक्रम का मंच संचालन अरविंद ओझा एवम् श्रीमती नमिता शर्मा ने किया. अतिथियों का आभार प्रदर्शन युवा अध्यक्ष अविनय दुबे ने किया. कार्यक्रम में प्रमुख रुप से महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा, महासचिव सुमन मिश्रा, सांस्कृतिक प्रभारी प्रीति मिश्रा, सुरभि शर्मा, बबीता मिश्रा, मिथिलेश रिछारिया, सुनीता शर्मा, साधना उपाध्याय, सुमन पांडे, कल्पना मिश्रा, वसुधा तिवारी, वीणा ठाकुर, सुलभा पाण्डेय, अर्चना तिवारी, गीतिका झा, अर्चना वोहरा, डॉ. स्नेहलता पाठक, डॉ. सुमन मिश्रा, अखिलेश्वरी शुक्ला, अर्पिता शर्मा, हर्षिता दीवान, रीता तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुणानिधी मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा, अजय अवस्थी, सुनील ओझा, नितिन कुमार झा, अविनय दुबे, रज्जन अवस्थी, संजय अवस्थी, पूर्व विधायक वीरेन्द्र पाण्डेय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अरुण शुक्ला, पूर्व सरपूपारीण अध्यक्ष दशरथ प्रसाद शुक्ला, अखंड ब्राह्मण अध्यक्ष योगेश तिवारी, मराठी ब्राह्मण अध्यक्ष डा. शेखर अमीन, इंजि. अशोक शर्मा, त्रिभुवन नाथ तिवारी, डॉ. दिलीप झा, प्रमोद गौतम, सतीष शर्मा, राघवेन्द्र पाठक, रामवृत तिवारी, शशिकांत शर्मा, उमेश शर्मा, नरहरि होता,रेखा पांडेय समाज सेविका रायपुर, बिलासपुर जिलाध्यक्ष रेखेन्द्र तिवारी, विमलेश तिवारी, गरियाबंद गिरीश शर्मा, बलौदाबाजार रमेश मिश्रा, शैलजा मिश्र आदि विशेष रुप से उपस्थित रहे।

### मुख्यमंत्री की 'हिंदू बाँटो' की रणनीति आम जनता भी समझने लगी है- विकास मरकाम

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा है कि प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 'हिंदू बाँटो' की रणनीति के तहत सरकार के मंत्री कवासी लखमा का यह कहना कि 'आदिवासी हिन्दू नहीं हैं और हम आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड मांगते हैं', अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हिन्दुत्व की व्यापक अवधारणा को नकारने की शर्मनाक राजनीतिक विवशता का परिचायक है। श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सेनिया गांधी की चरण वंदना और चापलूसी में अपने पुरखों की विरासत और परम्परा को नकारकर मंत्री लखमा ने अपनी वैचारिक गिरावट का परिचय दिया है। भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि दरअसल सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक एजेंडा तय कर रखा है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को बाँटा जाए। उसी एजेंडे के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यक्रम में प्रदेश की भूपेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने यह बयान दिया है। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भूपेश बघेल और कांग्रेस के इसी हिंदू बांटो एजेंडे के तहत बस्तर में सरकार के प्रश्रय में धर्मांतरण करने वालों की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अब वे एकत्र होकर आदिवासियों पर हमले करने लगे हैं। नारायणपुर में 300-400 की संख्या में एकत्र होकर उन्होंने आदिवासियों पर हमले किए। फिर उस घटना की पुनरावृत्ति जगदलपुर के तोकापाल क्षेत्र में हुई। श्री मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 'हिंदू बाँटो' की रणनीति धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ-साथ आम जनता भी समझने लगी है। अब तो मुख्यमंत्री बघेल को सीधे सामने आकर हिंदुओं को बाँटने की मुहिम हाथ में लेकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनकी सरकार के मंत्री लखमा ने जो बोला, उसमें उनकी भी सहमति है।

# मन की बात कार्यक्रम में प्रेरणादाई चर्चाओं ने सबको उत्साह से भरा

## मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में 39 दिन की बच्ची के ऑर्गन डोनेशन की कहानी ने हैरान किया

**रायपुर।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के 99वीं कड़ी को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के जरिए हर महीने प्रधानमंत्री देशवासियों से संवाद करते हैं। 03 अक्टूबर, 2014 को विजयादशमी के अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। आखिरी मन की बात कार्यक्रम विगत 26 फरवरी को प्रसारित हुआ था। रविवार को मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान (ऑर्गन डोनेशन) पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों के परिवार से बात की। श्री मोदी ने कहा कि अंगदान करने वाले ईश्वर के समान हैं।39 दिन की बच्ची के ऑर्गन डोनेट करने वाले परिवार को मोदी जी ने प्रणाम किया।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम तौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो %नर्वस नाइंटीज्% को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन-जन के मन की बात हो, वहाँ की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए देशभर नागरिकों के सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है, जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं, जो बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं, कोई अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव-सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान देने में भी संकोच नहीं करते, इसलिए तो हमें बचपन से शिवि और दधीचि जैसे देह-दानियों की गाथाएँ सुनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन, किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है, तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में अंगदान के प्रति जागरुकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के पाँच हजार से भी कम प्रकरण थे, लेकिन 2022 में यह संख्या बढ़कर 15 हजार से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों और उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी नीति पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों के मूल निवास प्रमाणपत्र की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु-सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखरकर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। कश्मीर के विकास की चर्चा करते हुए वहाँ कमलनाल (कश्मीर में जिसे नागरू कहा जाता है) की खेती के प्रति वहाँ के निवासियों में बढ़ते रूझान को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सराहा। श्री मोदी ने माँ शारदा मंदिर के निर्माण सहित अन्य अनेक बिंदुओं पर भी चर्चा की।

# भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने की सेंधमारी

**रायपुर।** मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर नजर डाली जाए तो साफ हो जाएगा कि किस तरह से वो बीजेपी के मुद्दों को बिल्कुल भी उठने नहीं देना चाहती। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना, गौ उत्पादों की बिक्री, गोबर से बिजली के साथ ही राम वन गमन पथ योजना, माता कौशिल्या मंदिर जीर्णोद्धार समेत आदिवासी आरक्षण बिल के जरिए हर उस वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिस पर पहले बीजेपी की पकड़ थी। ऐसे में अब बीजेपी को नए वोट बैंक की तलाश है।

कांग्रेस मानती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अंदर हिंदुत्व को लेकर किसी तरह की चुनौती का सामना कांग्रेस को नहीं करना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी प्रदेश में आचार संहिता लगने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक ही सिर्फ राम नाम और हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल करती है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम करती है। प्रदेश के भाचा (भांजा)

यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। माता कौशिल्या के मंदिर के लिए भी कोई काम नहीं किए गए। हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का या अन्य कोई मुद्दा। इनको बीजेपी भुना चुकी है। अब इन मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाया जा सकता। बीजेपी को सिर्फ राम नाम से चंदा और वोट चाहिए।

बीजेपी प्रदेश सरकार के एजेंडे और भगवान राम को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को चुनौती नहीं मानती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुताबिक कांग्रेसी राम के रास्ते पर सच्चे रूप में आ जाए, दिखावे के रूप में नहीं। चुनाव में राम भक्त बनने की कोशिश ना करें। चुनावी हिंदू भक्त ना बनें। दिल में यदि है तो उसको प्रदर्शित करें।

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का मानना है कि बीजेपी को भी ये आभास हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए कट्टर हिंदूवादी नेता भी दूसरे धर्म और समुदाय को साधने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस का एक धड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद लगातार हिंदुत्व के क्षेत्र में काम हुआ है। प्रदेश में सीएम भूपेश जिस तरह से गायों के लिए योजनाएं लाए, उनसे बड़ा गौ भक्त कोई नहीं दिख रहा। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी के कई मुद्दों पर सेंधमारी की है, जिनमें से एक मुद्दा हिंदुत्व का भी है।

उचित शर्मा के मुताबिक बीजेपी को ये पता चल चुका है कि प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा अब काम नहीं आने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने उसमें सेंधमारी कर दी है। यदि बीजेपी ने मंदिर या गायों को लेकर कांग्रेस पर हमला किया तो कांग्रेस के पास एक बड़ा जवाब है। इसलिए आगामी चुनाव में बीजेपी को हिंदुत्व वाली राजनीति का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा।

राजनीति के जानकारों की मानें तो बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाली पार्टी रही है। हर बार बीजेपी अपनी रैलियों में कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देती है। लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी है। बीजेपी अब दूसरी जातियों और धर्म समुदाय के लोगों को साधने में जुटी है। इसके विपरीत कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर अपना अलग एजेंडा चला रही है। यानी प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक तो पुराना है ही लेकिन इस बार उन्हें हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करने का एडवांटेज मिल सकता है।

## मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

# अधिग्रहण का गोरखधंधा

इसमें दो राय नहीं के उद्योग-धंधे लगने चाहिए। शहरों में जमीन बची नहीं इसलिए कारखाने लगाने के लिए गाँवों का रुख किया जाता है ।और बहुत मान मनौवल और मुआवजा का प्रलोभन देने के बाद गाँव के सीधे-सादे लोग अपनी जमीन देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। सिक्स लेन, फोर लेन सड़क के लिए भी गाँवों की जमीन अधिग्रहित की जाती है और प्रभावित ग्रामीणों को तगड़ा मुआवजा भी दिया जाता है .यह सब अगर सहमति के साथ हो तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब जोर-जबरदस्ती के साथ, धोखाधड़ी करके ग्रामीणों की जमीन हड़पी जाती है,तब दुख होता है । तब हमें कहना पड़ता है यह तो लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है । दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में यह खेल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यदा-कदा ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं। जनसुनवाई के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। कुछ गांवों में जनसुनवाई के लिए उद्योगपति पहुंचते हैं, गांव के लोग रहते हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी रहता है। ग्रामीणों में दहशत पैदा करके दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। और गांव में ही दो- चार दलाल किस्म के लोग भी होते हैं, जो बड़ी चालाकी के साथ जनसुनवाई में इस तरह से दर्शाते हैं कि जमीन अधिग्रहण करने के लिए पूरे गांव की सहमति बन गई है ।जबकि ऐसा होता नहीं है .गांव के लोग आज भी जागरूक हैं .अपनी अस्मिता के प्रति सजग हैं। वे गांव के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं इसीलिए कई बार खुलकर विरोध करते हैं । जैसा अभी हाल ही में सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में हो रहा है। वहां चिरगा अल्यूमिनियम प्लांट लगाए जाने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। लेकिन वहां के ग्रामीण प्लांट का विरोध कर रहे हैं। वे लाठी-डंडों और तीर-धनुष से लैस होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि प्लांट लगने से गांव की सेहत पर असर होगा। दूसरी बात, कारखाने के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है, वहां अनेक लोग पहले से ही रह रहे हैं । ग्रामीणों को समझाने के लिए प्रशासन भी पहुंच रहा है, लेकिन गांव के लोग मानने को राजी नहीं हैं हजारों ग्रामीण वहां एकत्र हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं। यह तो अच्छी बात है कि प्रशासन के लोग वहां हथियारों के साथ नहीं पहुंचे, वरना उत्तेजना और अधिक बढ़ती और अप्रिय स्थिति भी बन सकती थी। मैं यहां प्रशासन की सराहना करूंगा कि कलेक्टर आदि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहुंचकर आंदोलन स्थल तक पहुंचे और ग्रामीणों को समझाते रहे। यह बात मुझे ठीक लगी कि कलेक्टर ने कहा, हम कंपनी के प्रतिनिधि नहीं, शासन के प्रतिनिधि हैं। यहां हम किसी तरह के हथियार लेकर नहीं आएंगे । कलेक्टर के कदम की जितनी सराहना की जाए, कम है। लेकिन भविष्य में भी इसी सोच पर कायम रहना चाहिए। ग्रामीणों की अपनी जमीन है। उनकी अपनी मर्जी है कि उसे दे या ना दें। ठीक है कि विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है। सरकार कर भी सकती है लेकिन तभी कर सकती है जब बाजार रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ग्रामीणों की अपनी उनकी अपनी सहमति भी हो । उनको दूसरी जगह स्थापित किया जाए। उनको उतनी जमीन भी देनी चाहिए, जितनी उनसे ली जा रही है। न्याय तो यही कहता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। गांव वालों को बहला-फुसलाकर जमीन हड़प ली जाती है। कहा जाता है कि आपको मुआवजा देंगे। आपके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। ढाई दशक पहले सूरजपुर के पास भैयाथान क्षेत्र में एसईसीएल वालों ने कोयला खदान के लिए ग्रामीणों से जमीन ली और उनसे वादा किया, उनको नौकरी भी दी जाएगी और मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन देखते-देखते दो दशक साल बीत गए, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया और न ही नौकरी मिली। आज तक वहां के लोग दर-दर भटक रहे हैं। लेकिन प्रबंधन ने सिवा आश्वासन के और कुछ नहीं दिया। नवा रायपुर में भी अनेक ग्रामीण सही मुआवजे के लिए अब तक संघर्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जनता को ठगने की कोशिश हर तरफ से होती है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों का यह फर्ज है कि वे ऐसा न होने दें । जनता ही सरकार को चुनती है इसलिए सरकार का दायित्व है कि जन भावनाओं का सम्मान करे।और अगर जनता विरोध कर रही है तो उनकी जमीन को जबरन अधिग्रहित न किया जाए। और अगर बहुत जरूरी है भी तो उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जाए और उनके आवास के विकल्प में पर्याप्त जमीन भी आवंटित की जाए । अल्यूमिनियम प्लांट के लिए जमीन कंपनी को तब तक नहीं दी जानी चाहिए, जब तक बतौली गाँव के लोग तैयार नहीं होते। उनके आक्रोश को प्रशासन झेले। ऐसा न हो कि उनका दमन करने के लिए बल का इस्तेमाल करने लग जाए।

# 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा धान तस्करी न्याय योजनाः अजय

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि धान खरीदी की लिमिट 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की घोषणा धान तस्करी न्याय योजना हैं। श्री चंद्राकर ने कहा कि सन 2021 के आंकड़े बताते हैं कि रायपुर में धान की अधिकतम उत्पादकता 17.58 क्विंटल और न्यूनतम उत्पादकता 07.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका साफ मतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार धान खरीदी की लिमिट बढ़ाकर जनता को भ्रमित कर रही है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार सन् 2022 और 2023 की धान उत्पादकता के जिलेवार ताजा आंकड़े प्रदेश के समक्ष रखे। धान उत्पादकता अब तक उपलब्ध के आंकड़ों के मद्देनजर प्रदेश की बघेल सरकार की धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की घोषणा राजनीतिक और कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धान की तस्करी करने के लिए लुटाया जाएगा ताकि कांग्रेसी इससे भी अपना खजाना भर सकें। यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। यदि कहीं पर भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता तो भाजपा भी इसका समर्थन करती। श्री चंद्राकर ने कहा कि जब सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं है, तब प्रदेश की जनता इस पूरी योजना को समझे कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार करने जा रही है? किस तरह से यह कांग्रेस सरकार धान की तस्करी को बढ़ावा देना चाह रही है? श्री चंद्राकर ने प्रदेश की जनता और किसानों से अनुरोध किया है कि वह जागरूक होकर प्रदेश के खजाने को बचाएं। उन्होंने (श्री चंद्राकर ने) इसीलिए विधानसभा में कहा था कि प्रदेश का बजट कांग्रेस का बजट है न कि जनता का बजट है।

### कृषक को तस्कर कह कर अपमानित कर रहें हैं भाजपाई

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार के द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा 20 क्विंटल किए जाने से पूर्वाग्रह से ग्रसित भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ के किसानों को तस्कर करार देकर अपमानित कर रहे हैं। विगत 4 वर्षों में भूपेश सरकार के किसान हितैषी निर्णयों के चलते छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। कृषि विकास दर भी देश की तुलना में लगभग दोगुनी है, 2021 देश में कृषि विकास दर 3.50 है वही छत्तीसगढ़ में 5.93 है। ना केवल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की मात्रा बढ़ी है बल्कि पंजीकृत किसानों की संख्या 15 से बढ़कर 26 लाख और खेती का रकबा भी लगभग 10 लाख हेक्टेयर बढ़कर 31.17 लाख हैक्टेयर हो गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि से भाजपाइयों को पीड़ा हो रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान के अनुकूल जलवायु और परिस्थितियां हैं यहां सिंचित और असिंचित क्षेत्र में धान के उत्पादन के आंकड़े अलग-अलग हैं। जांजगीर, रायगढ़, धमतरी, कुरूद और रायपुर जिलों में भेट मुलाकात के दौरान किसानों ने धान खरीदी में प्रति एकड़ सीमा 20 क्विंटल करने की मांग प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करते रहे थे।

# हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सौम्या चौरसिया मामले की सुनवाई

**बिलासपुर।** कोल परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे अब भी जेल में बंद हैं। सौम्या चौरसिया अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन जज के याचिका की सुनवाई पर इंकार करने के बाद अब यह याचिका अन्य जज की बेंच में रखी गई है। इस पर अप्रैल की 29 तारीख को सुनवाई होगी। कुछ महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने सुर्खियां बटोरी थी। तब राज्य के कोल माफिया और राज्य के कई प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में ईडी ने कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की थी। राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया। तब से वह रायपुर की जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर की अदालत

में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जब जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में याचिका रखी तो उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया।

### गृहमंत्री के बयान का नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर किया खंडन

**बीजापुर।** गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी कर आरोप लगाते हुए कहा कि गृहमंत्री सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ यह कहकर भड़का रहे हैं कि नक्सली देश विरोधी और आतंकवादी हैं। प्रेस नोट में कहा गया है कि हमारा युद्ध सीआरपीएफ के खिलाफ नही बल्कि शासक वर्ग और उस हुकूमत के खिलाफ है जो जनता पर अत्याचार करते हैं। नक्सली प्रवक्ता ने गृहमंत्री के उस बयान का भी खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद से जंग आखिरी चरण पर है, और आदिवासी विकास में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। गृहमंत्री का दौरा सिर्फ सीआरपीएफ को आदिवासीयो के खिलाफ भड़काने के लिए था। नक्सली प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ दो सालों में 53 कैम्प स्थापित कर सम्पूर्ण बस्तर के सैनिकीकरण कर दिया गया है। उन्होने कहा कि गृहमंत्री के इस दौरे के बाद नक्सल प्रभावित इलाको में हवाई हमले के तेज होने की आशंका व्यक्त की है।

## छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

### मोदी कहते है देश बदल रहा हकीकत में देश बिक रहा -मोहन मरकाम

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम राजनांदगांव में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल हुये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र में बैठी है मोदी सरकार का दिखावे का नारा है देश बदल रहा है लेकिन सच्चाई यह है देश बदल नहीं रहा देश बिक रहा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपने जनता से किए वादों को निभाने का जो फर्ज निभा रही है जिससे छत्तीसगढ़ में सर्वहारा वर्ग खुशहाल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार की विफलता के कारण कमरतोड़ महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल यहां तक कृषि यंत्रों के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो गयी। बढ़ती महंगाई को रोक पाने में मोदी सरकार पूरी तरह विफ्ल है जिसका खामियाजा आम जनता भुगतना पड़ रहा है। हम दो हमारे दो के तर्ज पर चल रही केंद्र की मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए पूरे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम प्रारंभ कर दी है।

### मोदी सरकार की नीति के कारण उद्योग संकट में- कांग्रेस

**रायपुर।** मोदी सरकार की कोयला नीति के कारण छत्तीसगढ़ के उद्योगों का नुकसान हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता से कोयला उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को अनेकों बार पत्र लिखा लेकिन मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री के पत्र लिखने के 8 माह बाद भी राज्य के उद्योगों को कोयला उपलब्ध करवाने के लिये कोई निर्णय नहीं लिया। यह भाजपा की मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष 15 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में उत्पादित कोयले का अधिकांश भाग अन्य राज्यों में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। राज्य में अनेक बड़ी स्टील उत्पादक इकाईयों के अलावा सैकड़ों छोटी इकाईयां भी हैं जो लाखों लोगों की जीविका का आधार है। कोयले की कमी से राज्य के उद्योगों में बंदी का संकट मंडरा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 60 लाख टन कोयला प्रतिमाह एस.ई.सी.एल. द्वारा दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.50 करोड़ टन है।

### देश के भविष्य युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है - महेश गागड़ा

**बीजापुर।** युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित नेहरू युवा केन्द्र संगठन

की ओर से जिले के आडिटोरियम बीजापुर में जिला स्तरीय आस-पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के पूर्व केबिनेट मंत्री महेश गागड़ा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के रूप में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का आगाज युवाओं के प्रणेता रहे स्वामी विवेकानंद की चित्र पर दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ राज्य गीत के साथ किया गया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार,युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बलदेव उरसा,राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे,कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहें। मुख्य अतिथि महेश गागड़ा ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत देश का आने वाला भविष्य देश के युवाओं के हाथों में है, यही आगे जाके देश को उन्नति की ओर ले जायेंगे। लेकिन आप युवओं को एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाओ पर अपनी संस्कृति एवं विरासत को कभी मत भुलाना, यह हमारा कर्तव्य है।

### बेरोजगारी भत्ता के निर्णय से भाजपा घबराई - कांग्रेस

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा भूपेश सरकार द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के निर्णय से घबरा गयी है तथा अनर्गल बयान बाजी में उतर आई है। 15 साल तक युवाओं का शोषण करने वाली भाजपा किस मुंह से बेरोजगारी भत्ता देने बनाए गए नियमों पर सवाल उठा रही है? भाजपा को बेरोजगारी भत्ता पर सवाल पूछने से पहले दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के अपने वादा का विश्लेषण करना चाहिये और प्रदेश के युवाओं को बताएं की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल में प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया है? दो करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रदेश के 43 लाख युवाओ को रोजगार मिलना था नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिवर्ष दो करोड रोजगार देने में असफ्ल रही हैं और उल्टा मोदी सरकार की गलतियों नासमझी के चलते अब तक 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना जा चुका है। यानी प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 5 लाख 55 हजार 555 हाथों से रोजगार छीना गया है। मोदी सरकार की तरह ही पूर्व की रमन सरकार ने भी प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा और छल किया था 2003 में 12वीं पास युवाओं को 500 रू. प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर वादा पूरा नहीं किया था और उल्टा सरकारी नौकरी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचकर प्रदेश के युवाओं को हक अधिकार से वंचित किया था। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था।

### भाजपा ने पूछा- बेरोजगारी भत्ता देने पंजीयन के लिए पात्रता या अपात्रता सूची?

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियम व शर्तें बेरोजगार युवकों के साथ छल-कपट का एक और दांव है।

श्री शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस तरह से मापदंड प्रदेश सरकार ने तय किए हैं, उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को न तो रोजगार के अवसर देने की मंशा रखती है और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का उसका कोई इरादा है। श्री शर्मा ने सवाल किया कि बेरोजगारी भत्ता देने का नाटक करने वाली प्रदेश सरकार ने पंजीयन के लिए पात्रता सूची निकाली है या अपात्रता सूची? भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट ऐसे सारे विषयों में पंजीकृत लोगों के परिवारों के युवा, पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर जमाकर्ता परिवार के युवा, 10 हजार रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के युवा, बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवा को स्वरोजगार या निजी/सरकारी क्षेत्र में रोजगार का ऑफर आता है और उसे किन्हीं कारणों से अस्वीकार करने वाले युवा, केन्द्र या राज्य के तृतीय या इससे ऊपर की श्रेणी में नौकरी करने वाले परिवार के युवा बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अपात्र बनाए गए हैं।

# आदमखोर बाघ का खौफः हमले में ग्रामीण की मौत, स्कूलों में अवकाश

**सूरजपुर।** छत्तीसगढ़ के सरहदी जिले सूरजपुर में बाघ का खौफफैल गया है। लोग अब उसे आदमखोर भी कहने लगे हैं। आज सुबह ओड़गी ब्लाक में बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गयी, वहीं दो की हालत गंभीर है। इधर बाघों के खौफ के बीच स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ओड़गी बीईओ ने सभी संकुल प्राचार्य व जन शिक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि संवेदनशील क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को आने से मना करें। बीईओ ने आदेश में कहा है कि बाघ के लिए वन विभाग रेस्क्यू कर रहा है। जैसे ही बाघ का रेस्क्यू हो जायेगा, ये आदेश समाप्त हो जायेगा। गौरतलब हो कि कि सूरजपुर जिले में ओड़गी ब्लाक के ग्राम कालामांजन में बाघ के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है,जबकि दो लोग बुरी तरह जख्मी है,जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है,घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। कुदरगढ़ के नजदीक हुई इस घटना से इलाके में दहशत की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कालामांजन निवासी समय लाल कैलाश सिंह और राय सिंह जंगल की ओर लकड़ी लेने जा रहे तभी अचानक बाघ ने हमला कर दिया जिससे समयलाल कि मौत हो गई जबकि दो लोग जख्मी हो गए है।वन विभाग के मुताबिक क्षेत्र में तेंदुए के आहट की खबरे है वैसे में यह साफनही है कि हमला बाघ ने किया है या फिर तेंदुए ने। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है खास कर चैत्र नवरात्र कुदरगढ़ मेले में जहाँ लोगो का भारी जमावड़ा है। कूदरगढ़ महोत्सव शुरु होने वाला है ऐसे में इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बहरहाल बाघ की रेस्क्यू वन विभाग कर रहा है।

# तम्बाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

## कोटपा 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) एक्ट 2021 एवं पेका- 2019 की दी गई जानकारी

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल

अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई छत्तीसगढ़ एवं ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यशाला में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) एक्ट 2021 एवं ई सिगरेट प्रतिबंध एक्ट 2019 के प्रावधानों की जानकारी देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया कि तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। बावजूद इसके प्रदेश में स्कूली बच्चे तम्बाकू और ई-सिगरेट के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.10 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है। इस पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू मुक्त संस्थान हेतु दिशा-निर्देशों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्यतः लागू किया जाना है। द यूनियन संस्था के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ. अमित यादव ने छत्तीसगढ़ में ब्लूमबर्ग पहल परियोजना कार्यान्वयन पर तम्बाकू विज्ञापन और सचिव स्वास्थ्य चेतावनी के उल्लंघन पर कार्रवाई और इसमें आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में द यूनियन एवं पहल फाउंडेशन के माध्यम से टोबेको मॉनिटर एप का संचालन किया जा रहा है। पहल फाउंडेशन के तकनीकी सलाहकार आशीष सिंह ने टोबेको मॉनिटरिंग एप के बारे में तकनीकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रणजीत सिंह एवं भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ के प्रोग्राम मैनेजर बिनॉय मैथ्यू ने ई-सिगरेट प्रतिबंध एक्ट (पेका) 2019 और हुक्का बार प्रतिबंध कोटपा एक्ट- 2021 के क्रियान्वयन पर जानकारी दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.